

दैनिक

राज्यल पत्रिका

वर्ष : 13 अंक : 207 पेज : 8 जयपुर, रविवार 06 जुलाई 2025 मूल्य : 1.50 रुपये

अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन किया

दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोळ, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने त्रिभुवन दास पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चार साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के करोड़ों गरीबों और ग्रामीणों के जीवन में आशा का संचार करने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता क्षेत्र के विकास, संवर्धन और समविकास के लिए 60 नई पहल की हैं। शाह ने कहा कि ये सभी पहल सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव, पारदर्शी, लोकतांत्रिक बनाने, विकसित करने, सहकारिता के माध्यम से

किसानों की आय को बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए की गई। अमित शाह ने कहा कि आज यहां 125 एकड़ में 500 करोड़ रूपय की लागत से देश के पहले त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में रह गई सभी कर्मियों को पूरा करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देशभर में सहकारिता आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक युगांतरकारी कदम है। आज देशभर में 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं, 80 लाख बोर्ड्स के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, यानी देश का हर चौथा व्यक्ति, सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता के कर्मचारियों और सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले को ऑपरेटिव में भर्ती के बाद कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी



बनने के बाद जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उसी को नौकरी मिलेगी। शाह ने कहा कि इसके कारण सहकारिता में भाई-भतीजावाद खत्म हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी और जो सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित होकर निकलेगा, उसी को सहकारी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में युवा तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के सारे गुण तो सीखेंगे ही, साथ ही उन्हें सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे कि सहकारिता आंदोलन देश के दलित, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी से हो जाएगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जिस मेगा वैक्यूम ने हमारे सहकारिता आंदोलन को सिकोड़कर रख दिया था उसे भरने का काम यह यूनिवर्सिटी करेगी जिसके कारण अब सहकारिता आंदोलन फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा और भारत पूरे विश्व में सहकारिता का गढ़ बनेगा। त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी, यहां बनाई हुई नीतियां और अभ्यासक्रम, सहकारिता के आर्थिक मॉडल को एक जनआंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में युवा तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के सारे गुण तो सीखेंगे ही, साथ ही उन्हें सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे कि सहकारिता आंदोलन देश के दलित, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी से हो जाएगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जिस मेगा वैक्यूम ने हमारे सहकारिता आंदोलन को सिकोड़कर रख दिया था उसे भरने का काम यह यूनिवर्सिटी

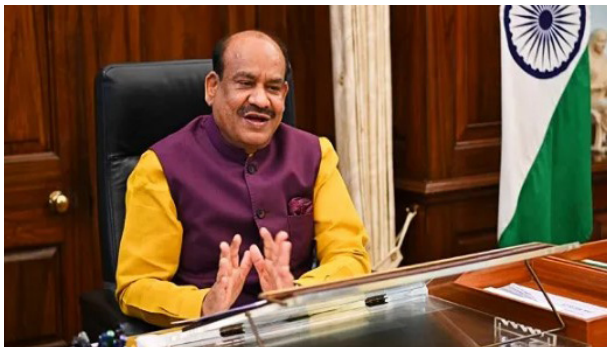
भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सस्ती है: लोकसभा अध्यक्ष -भारत फार्मा और चिकित्सा शोध के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है- ओम बिरला

दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सस्ती है। उन्होंने चिकित्सा आधारभूत ढांचा और सेवा वितरण में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि यह हर नागरिक की पहुंच में रहे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में की गई अनेक पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी और रोगी केंद्रित बनाया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और किफायती उपचार विकल्पों में हुई प्रगति की सराहना की और एक मजबूत और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बिरला ने नई दिल्ली में नवाचारी चिकित्सक मंच के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन - आईपीएफ मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन करते हुए यह उल्लेख किया।

बिरला ने कहा कि आज जब विकसित देश बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भारतीय चिकित्सक नवाचार और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मंच चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम शोध, उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए

एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है। यह पता लगाता है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरणों का उपयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने और चिकित्सा में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय डॉक्टरों की प्रतिभा और गुणवत्ता ने दुनिया में लोहा माना है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण, सेवा और बलिदान ने भारत को कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभावी जंग से प्रबंधन करने और सफल उपचार प्रदान करने में सक्षम बनाया था। बिरला ने उल्लेख किया कि यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की विश्वसनीयता का सच्चा प्रमाण है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा शोध के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, उन्होंने देश में दवा निर्माण, वैकसीन उत्पादन और जैव चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि भारत ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के दक्ष वैज्ञानिक, बेहतर शोध बुनियादी ढांचा और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय और वैश्विक दोनों जरूरतों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आगे



बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोध और विकास को बढ़ावा देने वाली पहल और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका को और मजबूत कर रहे हैं। बिरला ने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत जैसी पहलों के माध्यम से वंचितों के लिए शोध, नवाचार और मुफ्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार और शोध के महत्व का उल्लेख करते हुए इसे समय की मांग बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और रोगी देखभाल में सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति का लाभ उठाया जाना चाहिए। बिरला ने कहा कि नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना और चिकित्सा शोध के क्षेत्र में निवेश करना, नए उपचार विकसित करने, बीमारी की रोकथाम को बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने संस्थानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं से सहयोगात्मक रूप से काम करने का आग्रह किया ताकि ऐसी सफलताएँ प्राप्त की जा सकें जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक समुदाय को भी लाभान्वित कर सकें।

बिरला ने यह भी कहा कि यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं है - यह मानव सेवा के लिए एक वैश्विक मंच है। उन्होंने कहा कि शोध, नवाचार और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, आईपीएफ एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां होने वाली चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरण, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा - जो इस बात पर केंद्रित होंगी कि मानव-केंद्रित, कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कैसे बनाई जाए।

जयपुर में बिना परमिट बसों पर सख्त कार्रवाई, 3 लाख रुपए का जुर्माना

जयपुर। जयपुर में शनिवार को आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने बिना परमिट और तय रूट से हटकर चल रही बसों पर बड़ी कार्रवाई की। नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल और अजमेरी गेट इलाके में चेकिंग के दौरान करीब 20 बसों के चालान बनाए गए और एक बस को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई से विभाग को करीब 3 लाख रुपए जुर्माना वसूलने की उम्मीद है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बिना परमिट और तय रूट से हटकर शहर में आने वाली बसों पर अब हर जगह निगरानी रखी जाएगी। नियम तोड़ने पर बस संचालकों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई



भी होगी। इस अभियान के तहत शनिवार को टॉक रोड और आगरा रोड से आने वाली बसों पर भी कार्रवाई की गई। इन बसों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद ये बसें नियम तोड़कर शहर में घुस रही थीं। यह अभियान परिवहन सचिव

राजस्थान में बारिश का कहर: सवाई माधोपुर में 8 इंच बारिश, 4 की मौत

जयपुर। राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, नागौर, जयपुर और अजमेर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के कारण सवाई माधोपुर में स्कूल और बाजारों में घुटनों तक पानी भर गया। जिला कलेक्टर ऑफिस परिसर भी पानी से लबाब हो गया। सीकर में दुकानों और विधायक के घर में तेज बारिश के बीच अलग-अलग जगह डूबने से मां-बेटे समेत 4



लोगों की मौत हो गई। बारिश के चलते नदियों और बांधों में पानी बढ़ गया है। कोटा बैराज और कालीसिंह बांध से पानी छोड़ा गया, जबकि बीसलपुर बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को भी

मुंबई में मराठी भाषा विवाद पर हंगामा, बिजनेसमैन के ऑफिस में तोड़फोड़



मुंबई। मुंबई में मराठी भाषा को लेकर विवाद बढ़ गया है। शनिवार सुबह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने इन्वेस्टर सुशील केडिया के वर्ली स्थित ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में नारे भी लगाए। पुलिस ने मामले में MNS के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। यह हमला उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली से कुछ घंटे पहले हुआ। दरअसल, केडिया ने 3 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि वे मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मराठी नहीं सीखेंगे। इसके बाद MNS नेता संदीप देशपांडे ने उन्हें चेतावनी दी थी कि महाराष्ट्र में मराठी का अपमान करने पर तमाव पड़ेगा। ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद शनिवार को सुशील केडिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर राज ठाकरे और मराठी भाषी लोगों से माफ़ी मांगी है।

केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के लिए नए नियम जारी किए

-90 दिन में होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत देशभर की वक्फ संपत्तियों का रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस पर दर्ज किया जाएगा। अब वक्फ संपत्ति का प्रबंधक (मुतवल्ली) अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OAP से लॉगिन कर संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेगा। नई वक्फ संपत्ति बनने पर 3 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड पोर्टल पर वक्फ का रजिस्टर भी बनाए रखेगा। इन नियमों के तहत केंद्र और राज्य



सरकारों की जिम्मेदारी तय की गई है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी पोर्टल की निगरानी करेगा, जबकि राज्यों को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। पोर्टल में रियल-टाइम मॉनिटरिंग, कॉर्ट केस, विवाद निपटारा, ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय निगरानी और सर्वे से जुड़ी जानकारी भी

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी ने कहा- कर्ज चुकाना हमारा हक, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं

दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) का कर्ज चुकाना एक वैध कारोबारी फेसला था। हर कंपनी को अपना कर्ज उतारने का अधिकार है, और हमने भी वही किया है। AJL की संपत्ति का स्वामित्व अभी भी वहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। सिंघवी ने कहा कि AJL के 90 करोड़ रुपए के कर्ज को यंग इंडियन नाम की गैर-लाभकारी कंपनी ने लिया ताकि AJL कर्ज मुक्त हो सके। इसमें न कोई लैन-देन है, न धन का दुरुपयोग, इसलिए यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। उन्होंने सवाल किया कि अगर टाटा या बिरला जैसे बड़े कारोबारी घराने AJL का कर्ज चुकाते, तब भी क्या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगता?



उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई अधिकृत शिकायत दर्ज नहीं हुई, और सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में अधिकृत नहीं हैं। ED का आरोप: गांधी परिवार ने 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन कंपनी के जरिए AJL को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। एजेंसी का कहना है कि सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन के लाभार्थी हैं और उन्होंने धोखे से AJL पर नियंत्रण प्राप्त किया है। अगली सुनवाई में राहुल गांधी की दलीलें सुनी जाएंगी स्पेशल जज विशाल गोगने ने सोनिया गांधी की दलीलें सुनने के बाद अब अगली सुनवाई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दलीलों को सूचीबद्ध किया है।

जयपुर ज्वेलरी शो में दिलजीत दोसांझ का बेशकीमती पटियाला नेकलेस चर्चा में



जयपुर। जयपुर में चल रहे ज्वेलर्स एसोसिएशन शो (JAS) में मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का पहना पटियाला नेकलेस लोगों का ध्यान खींच रहा है। दिलजीत ने यह नेकलेस मेट गाला 2025 के दौरान न्यूयॉर्क में पहना था। इस नेकलेस को जयपुर के गोलछा ज्वेलर्स ने तैयार किया है, जिसे बनाने में 4 महीने से ज्यादा का समय लगा। यह डिजाइन पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह की ज्वेलरी से इस्पायर्ड है। इस सेठ की ज्वेलर ने नॉट फॉर सेल रखा है। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में शुकवार से शुरू हुए तीन दिवसीय शो में देश-विदेश से 2 हजार से ज्यादा व्यापारी शामिल हुए हैं। यहां जयपुर के बड़े ज्वेलर्स अपनी एंटीक और खास कारीगरी वाली ज्वेलरी शोकेस कर रहे हैं। शो में कई ऐसी ज्वेलरी भी दिखाई जा रही है, जिन्हें देश के अलग-अलग आर्ट और ट्रेडिशनल डिजाइनों के साथ मर्ज कर तैयार किया गया है।

हमास सीजफायर पर बातचीत को तैयार, इजराइल ने पहले ही मंजूरी दी

फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के सांगठन हमास ने कहा है कि वह इजराइल

के साथ 60 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव पर तुरंत बातचीत करने

को तैयार है। यह प्रस्ताव कतर ने दिया था। इजराइल ने भी इस प्रस्ताव को दो दिन पहले मंजूरी दे दी थी। हालांकि, पहले भी कई बार दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंचे, लेकिन आखिरी समय में बात नहीं बन सकी थी।

56 हजार से ज्यादा लोगों की मौत इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग में अब तक 56 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।

ट्रम्प ने चेतावनी दी थी इससे पहले ट्रम्प ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, वरना उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। सीजफायर प्रस्ताव में क्या है 10 जीवित इजराइली बंधकों की

रिहाई। 18 मृत इजराइली बंधकों के शव लौटाना। 60 दिनों का युद्धविराम, जिसके दौरान जंग खत्म करने पर बातचीत होगी।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

कॉलेजियम व्यवस्था में

पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी

अब हाईकोर्ट कॉलेजियम से आए नामों की सामान्य जांच के अलावा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अभ्यर्थियों की सामान्य जांच के अलावा इंटरव्यू से भी जोड़ दिया है। गत दिनों हाईकोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी प्रकरण और जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयानों ने लोगों के बीच न्यायपालिका के प्रति विश्वास को थोड़ा उगमगा दिया है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों नियुक्ति प्रक्रिया रबदली है। अब हाईकोर्ट कॉलेजियम से आए नामों की सामान्य जांच के अलावा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी ले रहा है।

यह कदम भ्रष्टाचार और न्यायपालिका को लेकर उठने वाले विवादों की रोकथाम की दिशा में सार्थक प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतना भर ही काफी होगा? क्या भारत को न्यायिक नियुक्तियों को लेकर वैश्विक मॉडल को अपनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 1993 और 1998 के फैसलों से विकसित हुई। यह प्रणाली, भी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर यदा-कदा आलोचना का शिकार होती रही है। अमरीका में संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नामांकन और सीनेट की मंजूरी से होती है, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई और गहन जांच शामिल होती है। हालांकि

इस प्रणाली में भी राजनीतिक दखल की आशंका बनी रहती है। यूरोप में, विशेषकर यूनाइटेड किंगडम में, स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग जजों का चयन करता है, जिसमें योग्यता, अनुभव और चरित्र की कठोर जांच होती है। भारत में वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, जिसमें सरकार और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा। यह कहा जा रहा था कि संरचना में हस्तक्षेप को आशंका रहने से ऐसा आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता था। फिर भी यह कहा जा सकता है कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की जरूरत है। इस योजना को सार्वजनिक करने, अभ्यर्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच के स्पष्ट मानदंड तो हो ही एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए, जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार की शिकायतों की जांच करे। निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक भर्ती प्रक्रिया में योग्यता-आधारित प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार शामिल करने होंगे। मोटे तौर पर भारत में जजों के चयन की ऐसी प्रणाली की जरूरत है, जो स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही का संतुलन बनाने का काम करे। इससे न केवल त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होगा बल्कि न्यायपालिका को जनता की आस्था का प्रतीक भी बनाया जा सकेगा।

मेक इन इंडिया; क्या भारत का आर्थिक पुनरुद्धार सही दिशा में है

- रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता: कितनी सफल रही मेक इन इंडिया योजना?

भारत एक युवा और महत्वाकांक्षी देश है, जो दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' योजना की शुरुआत की थी, तब देश में एक नई उम्मीद जगी थी कि भारत अब केवल एक उपभोक्ता देश नहीं रहेगा, बल्कि एक मजबूत उत्पादक और निर्यातक देश बनेगा। इस योजना का उद्देश्य देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और युवाओं को रोजगार देना था। आज जब इस योजना को एक दशक पूरा होने का रहा है, यह देखना जरूरी है कि इस योजना ने वास्तव में भारत के आर्थिक विकास में कितनी भूमिका निभाई है। इस योजना के बाद भारत में मोबाइल निर्माण में काफी उछाल आया है।

आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में निर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा है, और ड्रोन, हल्के लड़ाकू विमान और छोटे हथियारों का उत्पादन देश में ही होने लगा है।

आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में निर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा है, और ड्रोन, हल्के लड़ाकू विमान और छोटे हथियारों का उत्पादन देश में ही होने लगा है। इस योजना को सार्वजनिक करने, अभ्यर्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच के स्पष्ट मानदंड तो हो ही एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए, जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार की शिकायतों की जांच करे। निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक भर्ती प्रक्रिया में योग्यता-आधारित प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार शामिल करने होंगे। मोटे तौर पर भारत में जजों के चयन की ऐसी प्रणाली की जरूरत है, जो स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही का संतुलन बनाने का काम करे। इससे न केवल त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होगा बल्कि न्यायपालिका को जनता की आस्था का प्रतीक भी बनाया जा सकेगा।

दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फिर भी, यह कहना कि 'मेक इन इंडिया' पूरी तरह सफल हो गई है, जल्दबाजी होगी। इस योजना के तहत जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, यानी विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 25% तक पहुंचाना, वह अब भी पूरा नहीं हो सका है। तकनीकी और कुशल श्रमिकों की कमी, लॉजिस्टिक्स की अधिक लागत और नीतियों के कार्यान्वयन में राज्यों के बीच असमानता इस योजना की बड़ी चुनौतियां बनी रहीं। छोटे और मझोले उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है, जिसके कारण उनकी स्थिति मजबूत नहीं हो पाई है। इस बीच वैश्विक परिस्थितियों ने भी इस योजना को प्रभावित किया। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन ने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर डाला। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी और लाभ सीमित हुआ। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में अभी भी भारत को लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि चीन की उत्पादन लागत और उसकी आपूर्ति श्रृंखला आज भी भारत से कहीं अधिक सक्षम है।

फिर भी, इस योजना ने देश में उत्पादन और आत्मनिर्भरता की सोच को मजबूत किया है। इससे पहले भारत में जो चीजें केवल आयात पर निर्भर थीं, अब उनमें से कई चीजें देश में बनने लगी हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने भी देश में निवेश और उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है। अब जरूरत इस बात की है कि भारत में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को और तेज़ किया जाए, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए ताकि उत्पादन की लागत कम हो सके। इस योजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि देश अनुसंधान और नवाचार को कितनी प्राथमिकता देता है। भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में टिकने के लिए गुणवत्ता और

प्रतिस्पर्धा के स्तर को बनाए रखना होगा। इसके साथ ही उत्पादन में हरित तकनीकों को अपनाना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना भी जरूरी होगा ताकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी उद्योग स्थापित हो सकें। 'मेक इन इंडिया' केवल एक योजना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक मजबूत कड़ी है। इसके माध्यम से भारत ने दुनिया को यह दिखाया है कि वह उत्पादन में भी अपनी जगह बना सकता है। यह योजना भारत की आर्थिक आज़ादी और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे हमें मिलकर और आगे बढ़ाना होगा। अगर सरकार, उद्योग और समाज साथ मिलकर इसकी चुनौतियों पर काम करें, तो यह योजना देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है, और 2047 तक विकसित भारत का सपना हकीकत में बदल सकता है।

मेक इन इंडिया का उद्देश्य

विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 16% से बढ़ाकर 25% करना। 10 करोड़ रोजगार सृजन करना। विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना। 'इज़ ऑफ़ इंडिया बिज़नेस' को बेहतर बनाना। आयात पर निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भरता बढ़ाना। निर्यात को तेज गति से बढ़ाना। यह योजना 25 क्षेत्रों (ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, खनन, बायोटेक्नोलॉजी आदि) में लागू की गई थी। अब तक की उपलब्धियां FDI में वृद्धि: 2014 के बाद भारत ने FDI आकर्षित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।



2023-24 में भारत ने लगभग \$88 बिलियन का FDI आकर्षित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण और ऑटोमोबाइल में चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया से निवेश आया। मोबाइल निर्माण में सफलता: भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों ने उत्पादन यूनिट्स भारत में लगाई हैं।

रक्षा उत्पादन में प्रगति: भारत में रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ा है। ड्रोन, हल्के लड़ाकू विमान और छोटे हथियारों का निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है। रोजगार सृजन: औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रों में मेक इन इंडिया से जुड़े विनिर्माण में रोजगार बढ़ा, हालांकि आंकड़े मिश्रित हैं। 10 करोड़ रोजगार का लक्ष्य अभी दूर है, पर लाखों रोजगार निश्चित रूप से जुड़े हैं। निर्यात में वृद्धि: भारत का मैन्युफैक्चरिंग निर्यात बढ़ा है। 2024-25 में भारत का कुल माल निर्यात \$458 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स का योगदान अहम रहा।

चुनौतियां और कमियां जीडीपी में योगदान कम: निर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान अभी भी 17-18% के आसपास है। 25% का लक्ष्य दूर है। स्किल गैप: तकनीकी कुशल श्रमिकों की कमी एक बड़ी चुनौती रही। उद्योग को जिस स्तर के कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी, वैसी स्किल अपग्रेडेशन की गति धीमी रही। लघु उद्योगों पर दबाव: बड़ी विदेशी कंपनियों के आगमन से छोटे भारतीय उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ा, जिससे कुछ पारंपरिक उद्योग कर्मजोर हुए। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर: किर्ज़नेस करना आसान हुआ, लेकिन लॉजिस्टिक्स की लागत चीन और वियतनाम की तुलना में अभी भी अधिक है। नीति और कार्यान्वयन का अंतर: नीतियां बनीं, लेकिन राज्यों में उनका कार्यान्वयन समान रूप से नहीं हो सका। कई राज्यों में निवेशक अनुकूल माहौल नहीं बन सका।

वैश्विक चुनौतियां कोविड-19 महामारी: लॉकडाउन से उत्पादन और सप्लाई चैन पर असर पड़ा। यूक्रेन युद्ध: कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं, जिससे उत्पादन लागत प्रभावित हुई। चीन की सस्ती

आपूर्ति: चीन से प्रतिस्पर्धा अभी भी चुनौती है। **सकारात्मक संकेत** PLI स्कीम (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना): मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सौर उपकरणों में PLI स्कीम ने निवेश और उत्पादन को तेज किया है। उद्यमियों में आत्मनिर्भरता की सोच बढ़ी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण: भारत इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उत्पादन में तेजी ला रहा है। स्टार्टअप कल्चर: निर्माण से जुड़े स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं।

सफलता के कुछ क्षेत्र मोबाइल निर्माण में भारत ने चीन से आयात घटाया और निर्यात बढ़ाया। ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता में प्रगति। खिलौना निर्माण में भारतीय उत्पादन बढ़ा, चीन पर निर्भरता घटी। सौर पैनल निर्माण में भारत ने घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित किया। **असफलता के कुछ क्षेत्र** टेक्सटाइल सेक्टर में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं। कंप्यूटर चिप और सेमीकंडक्टर निर्माण में लक्ष्य से पीछे। रोजगार सृजन में लक्ष्य का लगभग 40% ही हासिल हुआ।

कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा, हकीकत क्या कहती है ?

पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार और प्रशासन कश्मीर में हालात के सामान्य होने का दावा करते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, आतंकी घटनाओं में गिरावट आई है और विकास की गति तेज हुई है। मगर क्या कश्मीर की सड़कों पर चहल-पहल, गुलमर्ग और पहलगाम में घूमते सेलानी, नए खुले हुए कॉफी शॉप और चमकती सड़कों का मतलब यह है कि वहां हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं?

सही है कि कश्मीर एक ऐसा मसला है, जिसे सिर्फ बाहरी तस्वीर देखकर नहीं समझा जा सकता। वहां की हकीकत को जानने के लिए घाटी की गलियों में, दूरदराज के गांवों में, स्थानीय लोगों की बातों में और उनकी खामोश नजरों में झांक कर देखना पड़ता है।

370 हटने के बाद का नया कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, तब सरकार ने कहा था कि यह कदम कश्मीर में शांति, विकास और आतंकवाद के खामे की दिशा में बड़ा कदम होगा। इसके बाद कुछ समय तक भारी पाबंदियां रहीं, संचार सेवाएं बंद कर दी गईं, नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद रहा। धीरे-धीरे पाबंदियां हटीं, इंटरनेट चालू हुआ, राजनीतिक गतिविधियां सीमित रूप में लौटने लगीं। अब प्रशासन दावा करता है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, निवेश आ रहा है, पर्यटक बड़ी संख्या में आने लगे हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मगर हाल ही में जिस तरह दक्षिण कश्मीर और जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उससे तस्वीर का दूसरा पहलू भी उजागर होता है।

पर्यटक तो आए, मगर डर बाकी है पिछले साल कश्मीर में रिकॉर्ड सेलानी पहुंचे। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में होटल फुल रहने लगे। शिकारे फिर से डल झील में सेलानियों को घुमाने लगे। सरकार ने इसे "नया कश्मीर" का प्रतीक बताया। यह



सही है कि पर्यटक लौटे हैं, मगर स्थानीय लोगों के मन में अभी भी डर बाकी है। घाटी के युवाओं के लिए रोजगार का संकट बना हुआ है। पर्यटक लौटने के बाद जो होटल, टेक्सटी, गाइड को रोजगार मिलता है, वह अस्थायी होता है। सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों की रफ्तार धीमी है। प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी अभी भी सीमित है। जो युवा पढ़े-लिखे हैं, उनके लिए स्थायी रोजगार का विकल्प अब भी नहीं बन पाया है। **सुरक्षा बलों की मौजूदगी, आम लोगों का असंतोष** घाटी में जगह-जगह चेकपॉइंट, बंकर और सुरक्षा बलों की तैनाती यह बताती है कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों की तलाशी, पहचान पत्र की जांच और आप दिनांक घरों में तलाशी अभियान से लोगों में असहजता बनी रहती है। कश्मीर के कई लोग कहते हैं कि "सम्राटा अमन नहीं होता।" कर्फ्यू या इंटरनेट बंद कर देने से अगर हिंसा कम भी हो जाए, तो यह स्थायी शांति नहीं कहलाती। असली शांति तब होगी जब लोगों के दिल से डर निकले, उन पर भरोसा उड़ा जा सके, और उन्हें भी भरोसा हो कि उनकी आवाज को सुना जाएगा। **राजनीतिक प्रक्रिया की धीमी वापसी** 370 हटने के बाद कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। पिछले साल राज्य का दर्जा फिर से देने और चुनाव कराने की बातें हुईं, मगर अब तक उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस बीच परिसीमन प्रक्रिया भी पूरी की गई, जिस पर स्थानीय दलों ने

सवाल उठाए। राजनीतिक दलों का कहना है कि अगर हालात वाकई सामान्य हो गए हैं, तो फिर चुनाव कराने में देरी क्यों? कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली ही असली सामान्य स्थिति का प्रतीक होगी। सिर्फ प्रशासक के जरिए सरकार चलाना या नाम मात्र की पंचायत चुनाव कराना स्थायी समाधान नहीं है। **हालिया आतंकी घटनाएं और बढ़ती चिंताएं** जम्मू-कश्मीर में बीते कुछ महीनों में डोडा, राजौरी, पुंछ जैसे इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती और तकनीकी निगरानी के बावजूद आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। सीमा पर से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं। **रोजगार, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक असर** कश्मीर में लंबे समय तक अस्थिरता रहने से बच्चों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है। कभी बंद, कभी इंटरनेट बंदी, कभी सुरक्षा कारणों से स्कूल बंद होने से शिक्षा में निरंतरता नहीं रह पाई। युवाओं के सामने रोजगार की कमी और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। अवासाद, चिंता और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

हज यात्रा में डिजिटल बदलाव भारतीय हज यात्रियों की नई चुनौतियां

हज इस्लाम का एक अहम फर्ज है, जिसे हर सामर्थ्य रखने वाला मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर अदा करना चाहता है। भारत से हर साल हजारों की तादाद में मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब रवाना होते हैं। यह यात्रा इबादत के साथ-साथ सन्न और अनुशासन का इम्तिहान भी होती है। बीते कुछ वर्षों में हज यात्रा में डिजिटल बदलाव ने व्यवस्थाओं को ज्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित और तेज बनाया है। ई-विजा, ऑनलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल भुगतान और स्मार्ट ट्रेकिंग जैसी व्यवस्थाओं ने हज यात्रियों की सहूलियतों को बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय हज यात्रियों के सामने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं, जिन पर बात करना बेहद जरूरी है ताकि यह पवित्र यात्रा हर यात्री के लिए आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बने।

हज यात्रा में डिजिटल बदलाव की शुरुआत ई-विजा और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया से हुई, जिसमें यात्रियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मोबाइल ऐप्स के जरिए घर बैठे आवेदन करने की सुविधा दी गई। इसके बाद सऊदी अरब ने स्मार्ट कार्ड और ई-ब्रेसेलेट देना शुरू किया, जिनमें यात्री की पहचान, स्वास्थ्य और लोकेशन की जानकारी मौजूद रहती है। 'नुसुक' जैसे मोबाइल ऐप्स ने यात्रियों को मक्का और मदीना में भीड़ प्रबंधन, आवागमन और जियातरत की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराई। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान और कैशलेस व्यवस्था ने यात्रियों को स्थानीय मुद्रा की समस्या से काफी हद तक निजात दिलाई। भारतीय हज मिशन ने भी यात्रियों की शिकायतों और उनकी लोकेशन मॉनिटर करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे त्वरित सहायता देना आसान हो गया है।

हज यात्रा में डिजिटल बदलाव क्या है? सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में हज और उमराह के संचालन में डिजिटल तकनीकों का उपयोग



बढ़ा दिया है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: ई-विजा और ऑनलाइन पंजीकरण- अब हज यात्रा के लिए ई-विजा प्रणाली लागू कर दी गई है, जिससे कागजी कार्यवाही कम हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से पंजीकरण की प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। स्मार्ट कार्ड और ई-ब्रेसेलेट- हज यात्रियों को स्मार्ट आईडी कार्ड और ई-ब्रेसेलेट दिए जा रहे हैं, जिनमें यात्री की पहचान, स्वास्थ्य जानकारी और लोकेशन ट्रेकिंग की सुविधा होती है। 'नुसुक' ऐप और डिजिटल गाइडेंस- सऊदी सरकार ने 'नुसुक' (पहले ई-हज) जैसे ऐप्स के माध्यम से भीड़ प्रबंधन, मार्गदर्शन, मक्का और मदीना में आने-जाने, और जियातरत की जानकारी डिजिटल माध्यम से देना शुरू किया है। कैशलेस व्यवस्था- सऊदी अरब में कई जगहों पर भुगतान डिजिटल मोड में होने लगा है, जिसमें कार्ड और ई-वॉलेट का प्रयोग बढ़ रहा है। **हज मिशन की मॉनिटरिंग भी डिजिटल** भारत का हज मिशन अब यात्रियों की समस्याओं, लोकेशन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग कर रहा है। **डिजिटल बदलाव के लाभ** पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी: डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन पंजीकरण से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है, जिससे यात्रियों को सही कीमत पर सेवाएं मिल

रहीं हैं। सुविधाजनक और त्वरित प्रक्रिया: पहले हज पंजीकरण के लिए लंबी लाइनें, फार्म जमा करना और अनुमोदन की प्रतीक्षा करना पड़ती थी। अब घर बैठे मोबाइल पर पंजीकरण और ई-विजा मिलना आसान हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि: स्मार्ट कार्ड और ट्रेकिंग से किसी यात्री के खो जाने पर उसे तुरंत ढूंढा जा सकता है। आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना आसान हो गया है। सूचना का त्वरित प्रसार: नुसुक ऐप और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल चैनलों से यात्रियों को तुरंत किसी भी बदलाव, चेतावनी या मार्गदर्शन की जानकारी दी जा सकती है। मिशन प्रबंधन में सरलता: भारत का हज मिशन और राज्य हज समितियां अब डेटा के आधार पर भीड़ प्रबंधन, बसों की सुविधा और आवास आवंटन को प्रभावी ढंग से कर पा रही हैं। **भारतीय हज यात्रियों के सामने नई चुनौतियां** हालांकि डिजिटल बदलाव हज यात्रा में सहूलियत लेकर आए हैं, लेकिन भारतीय हज यात्रियों के लिए ये कुछ नई चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रहे हैं: डिजिटल साक्षरता की कमी- भारत के छोटे कस्बों और गांवों से जाने वाले हज यात्रियों में बड़ी संख्या बुजुर्गों और तकनीकी रूप से अनभिज्ञ लोगों की होती है। उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण, ई-विजा डाउनलोड, ऐप्स का इस्तेमाल और डिजिटल भुगतान में कठिनाई होती है। भाषा की बाधा- नुसुक और अन्य

डिजिटल प्लेटफॉर्मों में अधिकतर अरबी या अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी, उर्दू या स्थानीय भाषाओं में इनका अभाव यात्रियों को सीमित कर देता है। बहुत से बुजुर्ग यात्री अरबी भाषाओं की समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। डिजिटल धोखाधड़ी का खतरा- डिजिटल भुगतान और ई-विजा प्रक्रिया के दौरान फर्जी वेबसाइट और दलाल सक्रिय हो जाते हैं, जो यात्रियों से पैसे वसूल कर उन्हें गलत जानकारी या फर्जी टिकट/वीजा दे देते हैं। कम डिजिटल जागरूकता वाले यात्री इनके जाल में फंस जाते हैं। तकनीकी खराबी और साइबर समस्याएं- ई-विजा डाउनलोड न होना, ऐप्स में लॉगिन समस्या, क्यूआर कोड न स्कैन होना जैसी समस्याएं हज यात्रियों को एयरपोर्ट से लेकर मक्का-मदीना में परेशानी में डाल देती हैं। हालांकि, इन बदलावों से लाभ मिलने के साथ ही भारतीय यात्रियों के लिए कई नई मुश्किलें भी सामने आई हैं। भारत के छोटे शहरों और गांवों से जाने वाले हज यात्रियों में बड़ी संख्या बुजुर्गों की होती है, जो स्मार्टफोन और डिजिटल प्रक्रिया में सहज नहीं होते। ऑनलाइन पंजीकरण, ई-विजा डाउनलोड, मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल और डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया उनके लिए चुनौती बन जाती है। कई बार भाषा भी बाधा बनती है क्योंकि नुसुक और अन्य ऐप्स अधिकतर अरबी या अंग्रेजी में होते हैं, जिनका इस्तेमाल हर यात्री के लिए आसान नहीं होता। इंटरनेट और स्मार्टफोन पर निर्भरता बढ़ जाने से ऐसे यात्री दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और कई बार गलत जानकारी या मददगार न मिलने की स्थिति में परेशान होते हैं। डिजिटल बदलाव की इस प्रक्रिया

में साइबर धोखाधड़ी और फर्जी वेबसाइटों का खतरा भी बढ़ गया है। डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर यात्रियों को पैसे वसूल कर लेते हैं और उन्हें फर्जी टिकट या गलत वीजा थमा देते हैं, जिससे उनका पूरा हज सफर खतरे में पड़ जाता है। तकनीकी समस्याएं जैसे ई-विजा डाउनलोड न होना, ऐप्स में लॉगिन में समस्या आना, क्यूआर कोड स्कैन न होना, या मोबाइल ऐप्स का अचानक बंद हो जाना यात्रियों के लिए एयरपोर्ट से लेकर मक्का-मदीना तक कई बार बड़ी समस्या बन जाती है। भीड़ और गर्मी के माहौल में ऐसे समय यात्री मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा, हज यात्रा के दौरान कैशलेस लेन-देन बढ़ जाने से भी कई यात्री खुद को असहज महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें नकदी पर निर्भर रहने की आदत होती है। इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। हज प्रशिक्षण शिविरों में यात्रियों को मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करना, ऑनलाइन प्रक्रिया समझना और डिजिटल भुगतान करना सिखाया जा रहा है। हज कमेटी ने हिंदी और उर्दू में हज मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जिनमें पंजीकरण से लेकर प्लानेट की जानकारी और दिशा-निर्देश तक दिए जा रहे हैं। राज्य हज समितियां हेल्पलाइन और वॉट्सएप हेल्प सपोर्ट शुरू कर चुकी हैं, ताकि यात्रियों को तत्काल सहायता दी जा सके। फर्जी वेबसाइटों और दलालों से बचने के लिए यात्रियों में जागरूकता फैलाई जा रही है और उन्हें सिखाया जा रहा है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप्स का ही उपयोग करें। हज मिशन में 'खादिम-उल-हुजाज के तौर पर वालंटियर्स की तैनाती भी की जाती है, जो बुजुर्ग यात्रियों की हर प्रकार की मदद करते हैं, विशेषकर डिजिटल प्रक्रिया में उन्हें मार्गदर्शन देने का काम करते हैं।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के गरीब व वंचित वर्ग के जीवन में आया बदलाव

-शिविरों में आमजन का विश्वास बदलते राजस्थान की तस्वीर- भजनलाल शर्मा

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्ग को आवास, बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन और बैंक खाते जैसी कई सुविधाएं मिली हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार देश के 94 करोड़ से अधिक लोगों को किसी ना किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है।

शेखावत शनिवार को जोधपुर जिले की शेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सोईतरा ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद दुनिया में भारत का गौरव और सम्मान बढ़ा है। आज का भारत समर्थ और सशक्त भारत है। हमने पहलगाय में निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों को घर में घुसकर मारा और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की उबल इंचन की सरकार ने पानी की उपलब्धता हेतु पूर्वी राजस्थान के

लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना और शेखावादी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैं, जिससे भविष्य में प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया गया, मगर भ्रष्टाचार के कारण ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो सका। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ किए जा रहे कार्यों से हमारा प्रदेश पूरे देश में समावेशी विकास का रोल मॉडल बनेगा। हमारा प्रयास है कि समाज का कोई भी व्यक्ति या परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में लोगों के चहरों पर नजर आ रहा विश्वास बदलते राजस्थान की तस्वीर है, जिसमें शासन और प्रशासन आमजन के द्वार आ रहे हैं और समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में बिजली, पानी, रोजगार एवं उद्योग क्षेत्र की प्रगति के लिए कई



कदम उठाए हैं। किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराना तथा युवाओं को पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियों देना हमारा लक्ष्य है। शर्मा ने कहा कि जोधपुर उस ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, जिसने मरुभूमि की आत्मा को सदियों से संजोया है। शेरागढ़ की धरती ने अपने नाम को सार्थक करते हुए हर युद्ध, हर अभियान में अपने शेर दिल सपूत मातृभूमि की सेवा के लिए भेजे हैं। गांवों को गरीबी मुक्त करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में भूमि-संबंधी विवादों का समाधान होने के साथ ही लोगों को अपनी भूमि का स्पष्ट

स्वामित्व मिल रहा है। किसान भाई-बहनों के लिए पौध वितरण, मृदा नमूनों के संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को मंगला पशु बीमा का लाभ देने के साथ ही पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड वितरित कर मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने की व्यवस्था की जा रही है। शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। हमने पहले चरण में 5 हजार गांवों को गरीबी मुक्त करने के लिए 300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

28 खसरे, 35 खातेदार...सहमति से खत्म हुआ 25 साल का इंतजार

- जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की मौजूदगी में पक्षकारों के बीच बनी सहमति

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत आयोजित हो रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर आमजन के लिए राहत का दूसरा नाम बन गए हैं। जहां ना केवल आमजन के काम हाथों हाथ हो रहे हैं बल्कि दशकों से राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद भी सहमति एवं समझाइश के माध्यम से सुलझ रहे हैं।

ऐसा ही एक ऐतिहासिक वाक्या देखने को मिला जयपुर के चोमू उपखंड के भूतेजा ग्राम पंचायत में, जहां आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में 25 सालों से 35 खातेदारों के बीच चले आ रहे 28 खसरे की 28 हेक्टेयर से अधिक भूमि विवाद का निस्तारण सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की मौजूदगी में पक्षकारों ने भूमि विभाजन पर सहमति प्रस्तुत की। बरसों पुराने राजस्व विवाद का

सौहार्दपूर्ण माहौल में निस्तारण के लिए सभी पक्षकारों ने मुख्यमंत्री भी भजनलाल शर्मा का आभार जताया, साथ ही प्रशासन की इस सकारात्मक पहल की भी सराहना की। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह राठी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को शिविरों के सफल संचालन एवं आमजन की परिचेष्टनाओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही



नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी है साथ ही, शिविरों के सफल संचालन करते हुए ज्यदा से ज्यादा आमजन को राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा पखवाड़े के तहत जिले के 16 उपखण्डों की 19 पंचायत समितियों की 461 ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। प्रतिदिन औसतन लगभग 35 ग्राम पंचायत में प्रातः 9:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक आयोजित हो रहे शिविरों में 16 विभागों द्वारा 63

कार्य किए जा रहे हैं। शिविरों का आयोजन दिनांक 07 जुलाई तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एवं दिनांक 8 जुलाई एवं 9 जुलाई को फॉलोअप केमप तहसील मुख्यालय पर किया जायेगा। जिला कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक नोडल अधिकारी, तकनीकी नोडल अधिकारी और उपखंडवार नोडल प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग व आरसीडीएफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

-प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश की 48 महिला दुग्ध समितियों की सचिव शामिल

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देशभर में दूसरे स्थान पर है, इसे अक्वल प्रदेश बनाने की दिशा में डेयरी के साथ-साथ गोपालन व पशुपालन विभाग की ओर से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। खासकर दुग्ध उत्पादन के लिए गिर गाय में ब्राजील से आयातित सीमन से क्रिमिंग गर्भाधान किया जा रहा है। इससे गिर गाय के दुग्ध के उत्पादन में दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रदेश में गाय की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सैक्स सॉर्टेड सीमन योजना को लागू किया गया है। ऐसा होने से प्रदेश में गौवंश की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। वे राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में पालमपुर (गुजरात) की बनास डेयरी परिसर में तीन

दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। डेयरी मंत्री कुमावत ने कहा कि प्रदेश के चार जिला दुग्ध संघों-जयपुर, सीकर, भरतपुर व टोंक की 48 महिला दुग्ध समितियों की सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण में महिला सचिवों को दुग्ध समितियों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल समिति का मुनाफा बढ़ेगा बल्कि महिलाओं की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण का लाभ महिला दुग्ध समितियों से जुड़ी प्रत्येक महिला को दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। डेयरी मंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। उन्होंने दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ावा दिए



जाने पर बल दिया। कुमावत ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होनी चाहिए। इसके लिए दुग्ध सहकारी समितियां प्रत्येक गांव में किसानों से संवाद स्थापित कर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र को किसानों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने के लिए डेयरी संघ बेहतर मॉडल विकसित करें। डेयरी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। मंत्री कुमावत ने बनास डेयरी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा

करते हुए कहा कि इसी प्रकार राजस्थान की सरस डेयरी भी इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी व आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बनास डेयरी के उपाध्यक्ष भावा भाई रबारी, बनास मंडिकल कॉलेज एंड ट्रस्ट के चैयरमैन पीजे चौधरी, बनास डेयरी के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी व प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्टर रामावतार सिंह आदि मौजूद थे।

बालकृष्ण गोयल ने जयपुर में विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने शुक्रवार को जयपुर शहर में कई संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर शहर स्थित गौंधीनगर में संचालित शिशु गृह एवं बालिका गृह का निरीक्षण कर संघर्षित रेकार्ड में पाई गई कमियों पर अधीक्षक को रेकार्ड का नियमानुसार संघर्षण करवा कर आयोग को अवगत करवाने के निर्देश दिए। गोयल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटगेट का भी निरीक्षण किया तथा उपस्थित

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुकुल कविया को दो दिवस के भीतर विद्यालय प्रांगण की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके कैंडिडर, प्रेरणास्रोत एवं लक्ष्य पर चर्चा की एवं गुट टच — ब्रेड टच के बारे में बताया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जिले के कुल विद्यालय एवं बच्चों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देते हुए विद्यालय की गरिमा पेटी को स्कूल विद्यालय की बाहरी दीवार पर चस्पा या पेंट करवाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र,



रैगरो की कोठी, संजय बाजार के निरीक्षण में विभागीय अधिकारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों का नामांकन बढ़ाने तथा गर्भती महिलाओं को दिये जाने वाला पोषाहार समय पर देने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम, जामडोली के निरीक्षण में व्यवस्थाएं सन्तोषजनक पाई गईं। इस पर गोयल ने कहा कि प्रशासन को ऐसी संस्थाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करना चाहिए। केन्द्रीय

कारागृह में भोजन एवं चिकित्सा व्यवस्था सन्तुष्टिजनक पाये जाने को, नवाचारों के माध्यम से जौनल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और बंदी एवं कर्मचारी कारागृह व्यवस्था से सन्तुष्टि जाहिर की।

विद्या भारती द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

-बौद्धिक और शारीरिक रूप में राष्ट्र को समृद्ध करने वाली शिक्षा की जरूरत -राज्यपाल

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राष्ट्र को बौद्धिक और शारीरिक रूप में सुदृढ़ करना आज के दौर की सर्वाधिक जरूरत है। विद्या भारती के शिक्षण संस्थान देश में इसी के लिए कार्य करते हैं। एलन मस्क के कहे की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी आज भारतीय इंजीनियरों की आवश्यकता है। राज्यपाल बागडे शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने ही जीरो की संख्या विश्वभर को दी। इसी से आगे की गिनती प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में भारत में पहला हवाई जहाज उड़ाया था पर विमान उड़ाने का श्रेय राइट बंधुओं को मिला। राज्यपाल ने विनोबा भावे के कहे की चर्चा करते हुए कहा कि जिस दिन देश में आजादी के बाद झंडा बदला गया, उसी दिन देश की शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए था। शिक्षा का भारतीयकरण होना

चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैकाले ने भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का प्रसार कर काले अंग्रेज तैयार किए। यह ऐसे हैं जो अपनी गौरवमय परंपरा से विमुख हैं। राज्यपाल ने कहा कि जितने गुरुकुल कभी भारत में थे उतने इंग्लैंड में विद्यालय नहीं थे। गुरुकुल में सर्वांगीण विकास की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में 16 भाषाएं सिखाई जाती थीं। आज तो तीसरी भाषा का भी विरोध किया जा रहा है। उन्होंने "पुत सिखावे पालने" कहावत की चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान में तो पालने में ही बच्चों को सिखाना प्रारंभ कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाना ही शिक्षाविदों का प्रमुख कार्य होना चाहिए। बागडे ने जर्मनी की चर्चा करते हुए कहा कि वहां प्राथमिक शिक्षा में सबसे अधिक वेंतन मिलता है। शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा से ही तैयार होती है। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में शिवप्रसाद ने कहा कि विद्या भारती संस्कार निर्माण के लिए देशभर में कार्य करती है। यह सामान्यजन के



लिए सामान्यजन द्वारा संचालित किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की सोच से कार्य करने की सीख विद्याभारती देती है। मुख्य अतिथि योगी रमण नाथ महाराज ने कहा कि शिक्षा में आइस्कू की दौड़ में इस्कू की अवहेलना की जा रही है। इसी से समाज में भावनात्मक संवेदनशीलता का तेजी से अभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि माइंड सेटअप बदलने से ही शिक्षा नीति की सफलता संभव होगी। जसवंत खत्री ने कहा कि सफलता

सार्थकता के साथ जुड़ेगी तभी वह महत्वपूर्ण होगी। पुलिस आयुक्तालय के अतिरिक्त आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने लक्ष्य को सर्वोपरि रखते हुए नई पीढ़ी को कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल बागडे ने प्रारंभ में विद्याभारती के प्रतिभावन विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने संस्कार राजस्थान के स्मृति अंक "जयदेव पाठक" का लोकार्पण भी किया। विद्याभारती के अध्यक्ष परमेश्वर दशोरा ने सभी का आभार जताया।

मदीना सबील कमेटी की पहल

सराहनीय है - लोहानी

मनोहरपुर, (रॉयल पत्रिका)। मजदूर नेता अजीज़ हबीब लोहानी ने कहा कि मदीना सबील कमेटी की पहल सराहनीय है। लोहानी ने कहा कि मदीना सबील कमेटी मोहरम के दौरान प्यासे लोगों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने के लिए सबील लगाती है, जो एक बहुत ही नैक काम है। अनवर तिगाला ने बताया कि सबील पर बज रही कव्वाली "पानी पीओ तो याद करो प्यास इमाम की" बहुत ही भावपूर्ण है और लोगों को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाती है।



मदीना सबील कमेटी की विशेषताएं - मोहरम के दौरान सबील लगाना - प्यासे लोगों को ठंडा पानी और शरबत पिलाना - सबील में हाथ की कलाकारी चमकी वह फूलों से सजाई जाती है - सामाजिक सेवा करना कार्य को अंजाम देने वाले अनवर तिगाला, शाहरुख तिगाला, रफीक साबु नीलगार, हमिद नीलगार, लाल नीलगार, आबिद गोरी मिरिंडा, कालू लोहार, मुस्तकीम तिगाला, रफीक जिंदरान आदि कई लोगों ने सबील के कार्य में भाग लिया। मदीना सबील कमेटी की गतिविधियों से न केवल लोगों को प्यास और गर्मी से राहत मिलती है, बल्कि यह कमेटी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी पहल से लोगों में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। उल्लेखनीय है कि अनवर तिगाला के नेतृत्व में पिछले 37 सालों से सबील लगाई जा रही है। तिगाला ने बताया कि अच्छी सेवाओं के फलस्वरूप हबीब खान लोहानी वेलफेयर सोसायटी सहित विधायक आदि सबील को सम्मानित कर चुके हैं।

खोखर ने किया हरसहाय मीणा और

जुगल किशोर मीणा का स्वागत



मनोहरपुर, (रॉयल पत्रिका)। जयवाराभागढ़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री जमील खान खोखर ने अपनी टीम के साथ हरसहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा का स्वागत किया। दोनों नेताओं को साफा बांधकर और माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया। **स्वागत समारोह में मौजूद रहे नेता** जमील खान खोखर के साथ रहमत खान मिलर, डॉक्टर ताहिर खान, जाहिद खान खोकर, इनायत खान, शेख बुंदू खान और सीलर भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने हरसहाय मीणा और जुगल किशोर

मीणा को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। **जमील खान खोखर की नेतृत्व क्षमता** जमील खान खोखर की नेतृत्व क्षमता और उनकी टीम की एकजुटता ने स्वागत समारोह को सफल बनाया। इससे पहले भी जमील खान खोखर ने हजरत हसन पीर चिश्ती रहमतुल्लाह अलेह के सालाना मेले में चादर पेश कर अमन चैन की दुआएं की थीं। उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

नगर निगम हेरिटेज आयुक्त ने देर रात किया

सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम हेरिटेज जयपुर की आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने गुरुवार देर रात शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चौड़ा रास्ता और जोहरी बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में रात्रिकालीन सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार बंद होने के बाद रात में सफाई की व्यवस्था की और मजबूत किया जाए ताकि दिन के समय यातायात बाधित न हो। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि मुख्य बाजारों की सड़कों से रात 12 बजे के बाद कचरा पूरी तरह उठवाया जाए और सफाई सुनिश्चित की जाए। इस निरीक्षण में गैराज शाखा की उपायुक्त सरिता मन्होत्रा, अधिशाषी अभियंता बलराम मीणा सहित अन्य निगम अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के



अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा आयुक्त निधि पटेल ने सिविल लाइन, सोडाला, गुर्जर की थड़ी और श्याम नगर इलाकों में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों से हो रही सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने डुलो मशीन की सफाई प्रक्रिया देखी और मशीनों में स्प्रेलिनर का उपयोग करने के निर्देश दिए ताकि सड़कों पर उड़ने वाली धूल नियंत्रित की जा सके। आयुक्त ने सफाई में लगे नए ड्राइवर्स को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए ताकि मशीनों का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।

आवश्यक नम्बर		रॉयल पत्रिका
विजली फॉल्ट के लिए		
टोल फ्री नंबर	18001806507	
वॉटरसप्लय नंबर	9414037085	
कन्सुमर केयर आईबीआरएस	22030000	
	1912	
कचरा गाड़ी के लिए		
ग्रेटर	2747400	
सीकर/ज लोकेश	2607500	
हेरिटेज	2607500	
टोल फ्री नंबर	14420	
पुलिस की मदद के लिए		
साइबर क्राइम	1930/2360094	
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38	
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098	
महिला हेल्पलाइन	1090	
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	
पानी के लिए		
जलदाय कार्यालय फायर ट्रिगेड	2706624	2747400
मैडिकल इमरजेंसी के लिए		
एंबुलेंस	102/108	
एसएमएस इमरजेंसी	2518333	
महिला चिकित्सालय	22610616	
अनना हॉस्पिटल	22376721	
SDMH	22574189	
SMS ब्लड बैंक	22518222	
कल्याण ब्लड बैंक	22721771	
घायल पशुओं के लिए		
नगर निगम	2747400	
बर्ड वाइक	9887345580	
हेल्थ इन सफरिंग	8107299711	
जनमंत्र ट्रस्ट	7230055800	
पशु चिकित्सालय	2747400	

जिला कलक्टर की अपील, भारी बारिश के चलते जलभराव वाले स्थानों से दूर रहें

सवाई माधोपुर, (राँयल पत्रिका)। जिले में भारी बारिश को देखते हुए जिला कलक्टर काना राम ने आमजन से जलभराव और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस समय सावधानी और सजगता ही जन-धन की हानि से बचाव का एकमात्र उपाय है। जिले में लगातार हो रही तेज वर्षा के कारण नदियों, तालाबों, एनिकटों, बावड़ियों, कुण्डों और झरनों में जलस्तर बढ़ रहा है तथा आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में निचले इलाकों और जलभराव संभावित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक विशेष सतर्कता बरतें एवं खतरा महसूस होने पर सुरक्षित स्थानों पर आगमन करें। आपात स्थिति में आमजन सहायता हेतु नियंत्रण कक्ष पर करें संपर्क:- जिला कलक्टर ने बताया कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। किसी आपात स्थिति में आमजन जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07462-220602, 07462-220201 या टोल फ्री नम्बर 1077 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं तहसील स्तर पर सवाई माधोपुर में तहसीलदार +91 8860683111, खण्डार तहसील में +91 7014451115, चौथ का बरवाड़ा तहसील में +91 7042836979, बौली तहसील में +91 9784538790, मित्रपुरा में +91 9413817621, मलारना डूंगर तहसील में +91 7742214562, गंगापुर सिटी तहसील में +91 8875777228, बामनवास तहसील में +91



6350209735, वजीरपुर तहसील में +91 7877734113, बरनाला तहसील +91 7982046924 एवम् तलावड़ा तहसील में +91 9887008003 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जल प्रवाह में प्रवेश न करें - वैकल्पिक मार्ग अपनाएं- जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों से बहने वाली नदियों-नालों में जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ता है। ऐसे में पुल-पुलियाओं, नदी-नालों या बहाव वाले मार्गों को पार करने का दुस्साहस न करें। यदि मार्ग पर पानी का बहाव है तो वैकल्पिक रास्ता चुनें या जलस्तर के कम होने तक प्रतीक्षा करें। "जिंदगी अनमोल है, छोटी सी गलती भारी नुकसान में बदल सकती है", यह कहते हुए उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सतर्कता बरतें और अनावश्यक जोखिम से बचें।

रील और सेल्फी के चक्कर में न डालें जान जोखिम में:- मानसून के साथ मौसम सुहावना जरूर हुआ है, लेकिन यह किसी भी प्रकार के रोमांच या सोशल मीडिया गतिविधि के लिए जान जोखिम में डालने का समय नहीं है। कलक्टर ने विशेषकर युवाओं और बच्चों से अपील की कि वे तेज बहाव वाले प्राकृतिक स्थलों, झरनों, पुल-पुलियों आदि पर रील और सेल्फी बनाने से परहेज करें। परिजनों को भी चाहिए कि वे बच्चों को इन स्थानों पर जाने से रोके। जलभराव से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां - एडवाइजरी जारी- जिला प्रशासन द्वारा आमजन के लिए महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है। जलभराव संभावित इलाकों से दूर रहें और पक्के, सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लें। अस्थायी एवं कमजोर ढांचों को सुरक्षित करें या खाली कर दें। तेज बारिश के समय फिसलन भरी सड़कों पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वाहन न चलाएं। जलमग्न अंडरपास, पुल-पुलियाओं एवं ओवरपल्स मार्गों से परहेज करें। जलभराव के दौरान बच्चों को बाहर खेलने या नहाने से रोके। बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें और खुले स्थानों, पेड़ों, खंभों आदि के नीचे खड़े होने से बचें। सुरक्षित और उबला या क्लोरिनयुक्त पानी ही पीने में उपयोग करें। जिला कलक्टर काना राम ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें और अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

बीएलओ चुनाव व्यवस्था की फील्ड पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

-मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की समीक्षा

शब्बीर हुसैन बारां/जयपुर, (राँयल पत्रिका)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स चुनाव व्यवस्था की फील्ड पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो मतदाता सूची की शुद्धता एवं निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। अतः उनकी नियुक्ति में कार्य कुशलता, प्रतिबद्धता और स्थानीय मतदाताओं से संपर्क जैसे गुणों को प्राथमिकता दी जाए। महाजन शुक्रवार को शासन सचिवालय में मतदान केंद्र रेशनलाइजेशन, मतदाता सूची पुनरीक्षण, बीएलओ नियुक्ति आदि विषयों पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोलिंग स्टेशन रेशनलाइजेशन का कार्य पूर्णतः मतदाता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाए। रेशनलाइजेशन इस प्रकार हो कि हर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आसान पहुँच,



मूलभूत सुविधाएं, दूरी आदि का संतुलन बना रहे। उन्होंने प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के लिए निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिक्त पदों पर बीएलओ की जल्द नियुक्ति की जाए और संभावित नए मतदान केंद्रों के लिए बीएलओ नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ करें। जिससे मतदाता सूची निर्माण में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन से संबंधित जानकारी सरलता एवं सुगमता से

आमजन तक उपलब्ध हो, इसके लिए विभिन्न प्रचार सामग्रियों एवं सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। जिससे हर वयस्क नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नए जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया को सुगमता से सम्पादित करने के लिए कुशल तंत्र विकसित किया जाये। बैठक में निर्वाचन विभाग के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बोलेरो के शराबी चालक ने कार को टक्कर मारी

-कार में सवार दो महिलाओं सहित चार जने गंभीर घायल

मोहम्मद अली पठान चूरू/रतनगढ़, (राँयल पत्रिका)। रतनगढ़ के पास बोलेरो के एक शराबी चालक ने गलत दिशा में चलकर एक कार को टक्कर मार दी, इससे कार में सवार दो महिलाओं सहित चार जने गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों जने अपने रिश्तेदार की शोक सभा से वापस घर जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिवस आर जे 18 यू ए 1953 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही से चलाकर सामने से आ रही एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बोलेरो का शराबी चालक और उसका साथी अपन वाहन को छोड़कर भाग गया। दुर्घटना में कार सवार दंपती श्रवण सिंह राठौड़ और मंजू कंवर, मुकेश सिंह और उनकी भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के चालक ने अपने वाहन से रतनगढ़ के अस्पताल में पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको सीकर रेफर कर दिया गया। श्रवण सिंह और मंजू कंवर को आज सीकर के टीबड़ा अस्पताल से गंभीर हालत में जोधपुर रेफर कर दिया गया। मुकेश सिंह और उनकी भाभी का सीकर में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जप्त कर लिया है।



जिला जेल, राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, यश दिव्यांग सेवा संस्थान, त्रिनेत्र बालगृह

-रूक्मणी वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं

सवाई माधोपुर, (राँयल पत्रिका)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार दिनांक 05.07.2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा जिला जेल सवाई माधोपुर का साप्ताहिक निरीक्षण कर जेल में निरूद्ध बंदियों से मुलाकात कर मुकदमों की पैरवी हेतु अधिवक्ता की उपलब्धता, भोजन, पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाओं तथा बैरकों एवं कारागृह परिसर की सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। सचिव समीक्षा गौतम द्वारा मुख्य प्रहरी महेश चन्द शर्मा को जेल मैनुअल के अनुसार सभी बंदियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा जेल से संबंधित सभी रजिस्ट्रारों को नियमित रूप से अपडेट करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। निरीक्षण के दौरान कारागृह में कुल 113 बंदी उपस्थित पाये गए। निरीक्षण के दौरान चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल (व्याय रक्षक) राधेश्याम जोगी, अधिकार मित्र सुमित्रा देवी एवं जेल स्टाफकर्मों उपस्थित रहे। इसी प्रकार जिला विधिक चेतना समिति के सदस्य हरिसिंह मीणा एवं मनीष तंवर द्वारा राजकीय



संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, यश दिव्यांग सेवा संस्थान, त्रिनेत्र बालगृह एवं रूक्मणी वृद्धाश्रम सवाई माधोपुर का निरीक्षण कर बालकों एवं वृद्धजनों को प्रदान भोजन, पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाओं, संस्थानों में स्टाफ की स्थिति, संस्थान में स्थित रसोईघर, स्नान घर, शौचालय आदि की साफ सफाई, बालकों एवं वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण, संस्थान में डॉक्टर की विजिट, संस्थान में प्राथमिक उपचार किट एवं अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, परामर्शदाता की सुविधा, आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में संस्थान में उपलब्ध सुविधा, बालकों एवं वृद्धजनों के साथ दुर्घटना को रोकने के

उपायों, संस्थान में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण बोर्ड पर अंकन, संस्थान में शिकायत पेटी की उपलब्धता, बालकों एवं वृद्धजनों के पूरे दिन का शेड्यूल, बालकों एवं वृद्धजनों की संख्या आदि के संबंध में निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण संस्थान में बालकों एवं वृद्धजनों को प्रदान मूलभूत सुविधाएं और संस्थान की साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई। दौरान निरीक्षण राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह में 13, यश दिव्यांग सेवा संस्थान में 47, त्रिनेत्र बालगृह में 20 बालक तथा रूक्मणी वृद्धाश्रम में पांच महिला एवं दो पुरुष सहित कुल 07 वृद्धजन उपस्थित पाए गए।

डॉक्टर मोहम्मद समीर ने समाज को गौरवान्वित किया

चूरू, (राँयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय के सुभाष चौक के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद समीर पिता मोहम्मद अली तगाला ने एमबीबीएस अजमेर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से किया और नई पोस्टिंग आपकी दिल्ली सचिवालय सीएम ऑफिस मेडिकल क्लिनिक पर है। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री राखी गुप्ता द्वारा क्लिनिक का उद्घाटन व निरीक्षण किया गया जिसमें डॉक्टर मोहम्मद समीर की नई पोस्टिंग पर बधाई दी। और डॉ.



समीर ने बताया कि चूरू में मेरे माता-पिता परिवार और समाज के सभी लोगों ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और आसिफ मं ड व र या, मोहम्मद रफीक चौहान ने उज्ज्वल भविष्य व कामयाबी की दुआएं की।

राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के स्टाफ की घोर लापरवाही आई सामने पाली, (राँयल पत्रिका)। स्कूल के नव प्रवेशित विद्यार्थी को ताले में बंद कर स्टाफ चला गया अपने घर, विद्यालय छुटी के समय नव प्रवेशित बच्चे को नींद आने से रह गया क्लास के अंदर, 2 घंटे बाद

बच्चों को भविष्य के हिसाब से गढ़े शिक्षक -शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

-बच्चा बड़ा होकर राम बनेगा या रावण ये शिक्षक के हाथ

शब्बीर हुसैन रातडिया/अंता, (राँयल पत्रिका)। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा ये स्कूल के शिक्षकों के हाथ में है। स्कूल में शिक्षक यदि अच्छा पढ़ाता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देता है तो वह बड़ा होकर आदर्श नागरिक बनेगा लेकिन यदि शिक्षक अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है तो बच्चों को नुकसान होता है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह है। वो बड़ा होकर राम जैसा बनेगा या रावण की तरह होगा ये शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। दिलावर शनिवार को अंता में महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय रातडिया में आयोजित पुस्तकालय कक्ष के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का विशेष जोर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर है। इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हमने प्रदेश के सभी 970 महात्मा गांधी विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारंभ कर दिए हैं ताकि बच्चों को विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए दूर नहीं जाना पड़े। हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य को लेकर प्रदेश के 96



उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। 99 विद्यालय में अतिरिक्त संकाय खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। जब सत्र के प्रथम दिन ही विद्यालय क्रमोन्नत करने और संकाय खोलने की आदेश जारी हुए हैं। 11576 शिक्षकों को महात्मा गांधी स्कूलों में लगाया गया है। ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। शीघ्र ही शेष रिक्त पदों को भी भर दिया जाएगा। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में नवनिर्मित पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन का लोकार्पण किया। यहां उपस्थित बच्चों से वार्ता भी की। इसके बाद विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया तथा स्कूल भवन में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण

भी किया। शिक्षा मंत्री दिलावर ने इस अवसर पर दानदाताओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में मंत्री दिलावर ने स्कूल में इंटरलॉकिंग के लिए 5 लाख रूपए देने की घोषणा की। इसके अलावा देवपुरा बंजारा स्कूल, अंता को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने, अलीपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के अगले वर्ष भवन निर्माण करने की घोषणा की। साथ ही पाटूदा स्कूल में संस्कृत विषय के अध्यापक लगाने के लिए पद सूचित करने के प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बारां को दिए। इसके अलावा इसी विद्यालय में उर्दू विषय के विद्यार्थी नहीं होने के कारण पदस्थापित उर्दू विषय के शिक्षक को तत्काल रिलीव करने के आदेश दिए।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविरों का आयोजन जारी

-31 हजार से अधिक लाभार्थी हुए लाभान्वित

बारां, (राँयल पत्रिका)। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि जिले में जनजातीय समुदाय के समस्याओं का समाधान एवं उर्दू विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत विशेष शिविरों का आयोजन जारी है। यह अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर 15 जून से शुरू हुए जो 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। जिसके तहत अब तक 138 से अधिक शिविरों का सफल आयोजन हो चुका है। इन शिविरों में 31 हजार 549 से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। एडीएम शाहाबाद जबर सिंह ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम

से जनजातीय परिवारों को आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, केसीसी, विभिन्न पेंशन योजनाएं, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान निधि, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, मनरेगा, राशन कार्ड, सिकल सेल टैस्टिंग, मूल निवास प्रमाण पत्र, मिशन इंद्रधनुष, मुद्रा योजना जैसे कुल 25 से अधिक योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

जिनमें अब तक 1243 आधार, 740 जाति प्रमाण पत्र, 744 आयुष्मान कार्ड, 50 किसान क्रेडिट कार्ड, 308 पेंशन योजना, 1741 पीएम गरीब कल्याण, 134 पीएम जनधन खाते, 48 पीएम जीवन ज्योति योजना, 293 पीएम किसान सम्मान निधि, 133 पीएम मातृ वंदन योजना, 5 पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 282 पीएम उज्ज्वला योजना, 210 पीएम विश्वकर्मा योजना, 740 राशन कार्ड, 569 सिकलसेल टैस्टिंग, 17 सुकन्या समृद्धि योजना, 274 मूल निवास प्रमाण पत्र, 773 मनरेगा, 124 मिशन इन्द्रधनुष योजना, 13 मुद्रा योजना का लाभ दिया गया। एडीएम सिंह ने सभी पात्र जनजातीय परिवारों से आग्रह किया है कि वे इन शिविरों में भाग लें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं को एवं अपने परिवार को सशक्त बनाएं, ताकि कोई भी हितग्राही लाभ से वंचित न रहे।

हाजी आरिफ खान दौलत खानी का रफीक मंडेलिया ने किया स्वागत



चूरू, (राँयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने वार्ड नम्बर 59 निवासी हाजी आरिफ दौलतखानी के हज के मुकदस सफर को मुकम्मल करके चूरू आगमन पर उनके निवास पर पहुंचकर शयोल, साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। रफीक मंडेलिया ने कहा कि हज एक इबादत ही नहीं, बल्कि एक तर्बियत है, यह हमें सत्र, अल्लाह की याद और इंसानियत की खिदमत सिखाता है। हज इस्लाम का एक बहुत बड़ा फर्ज है, जो हर उस मुसलमान पर

जिंदगी में एक बार वाजिब होता है, जो आर्थिक और शारीरिक तौर पर काबिल हो। इस दौरान पूर्व सभ्यपति गोविन्द अंधसरिया, पीसीसी सचिव रियाजत खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोशर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धाम्शू किसान नेता आदूराम न्यौल, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नारायण बालाण, जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान, जिला उपाध्यक्ष शिवकुमार शर्मा, अजीज दिलावरखानी, विमल शर्मा, समीउल्लाह गोरी, आरिफ रिसालदार, संजय भाटी, योगेश ढाका मौजूद रहे।

सीवरेज पाइप लाइन नहीं होने की वजह से मोहल्ले में फैली गंदगी

पाली, (राँयल पत्रिका)। सामाजिक कार्यकर्ता सरोज राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर पाली व नगर निगम आयुक्त को पत्र लिख कर वृद्धाश्रम पाली रेलवे स्टेशन के पास वाली गली महेश कॉलोनी में सीवरेज पाइप लाइन बिछा कर जनता को राहत देने की मांग की राजपुरोहित ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे महेश कॉलोनी में सीवरेज लाइन नहीं बिछाई हुई है गली सकरी होने के कारण कार्यकारी एजेंसी ने इस गली का कार्य नहीं किया। जिससे मोहल्ले वासियों को कई वर्षों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गली नीचे होने की वजह से नालिया भर पड़ी रहती है और पूरे मोहल्ला में गंदगी फैली हुई है लोगो का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है सीवरेज बिछाने वाली कंपनी ने गली के मुख्य सड़क तक पाइप लाइन लाकर छोड़ दी मगर महेश कॉलोनी में सीवरेज का काम नहीं किया जिससे बार बार सीवरेज की गाड़ी बुला कर पानी खाली करवाना पड़ता है। सरोज राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर और आयुक्त से पुर जोर मांग की है कि जनहित में वृद्धाश्रम के पास वाली महेश कॉलोनी में सीवरेज लाइन बिछा कर मुख्य पाइप लाइन से जुड़ाने की कार्यवाही कर कई वर्षों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गली नीचे होने की वजह से नालिया भर पड़ी रहती है और पूरे मोहल्ला में



कलक्टर काना राम ने किया चौथ का बरवाड़ा शिविर का निरीक्षण

-300 से अधिक मामलों को हुआ समाधान

सवाई माधोपुर, (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित शिविर का जिला कलक्टर काना राम ने आकस्मिक निरीक्षण किया।

शिविर के दौरान जिला कलक्टर, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को कार्यों से संबंधित दस्तावेजों, आयुष्मान कार्ड, मूद्रा स्वास्थ्य कार्ड तथा आवासीय पट्टे स्वीकृतियां आदि का मौके पर ही वितरण किया गया। शिविर में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 3 पट्टे का वितरण, 15 मूद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए, 72 टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान की और 36 नामांतरण प्रकरणों को मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं समाज कल्याण द्वारा 34 पेंशनरों, एनएफएसए के 141 आवेदनों, 120 परिवारों की आधार सीडिंग करवाई गई। उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन शिविरों में राजस्व, शिक्षा, पशुपालन, डिस्कॉम, पीएचडीई, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, रसद, कृषि सहित विभिन्न विभाग के बिजली के



झूलते तारों को खिचवाना, लंबित नल कनेक्शन शीघ्र जारी करना, लंबित नामांतरणों का निस्तारण, रास्ते के प्रकरणों का निस्तारण, नर्सियों से पौधों का वितरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण, मंगला पशु बीमा का लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन सहित विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक आमजन से इन शिविरों के तहत करवाए जा रहे कार्यों का लाभ उठाने एवं अन्य को भी प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने शिविर में मौजूद विभागीय अधिकारियों से आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने, विशेषयोजनों के पेंशन सत्यापन के लिए ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन कराने के निर्देश ग्राम विकास अधिकारी

को दिए। उन्होंने जलापूर्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर टंकियों की नियमित साफ-सफाई करने, सप्लाई लाईन की लीकेज दुरुस्त करवाकर अंतिम छोर तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा को प्रवेशोत्सव के दौरान सभी राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक बच्चों के प्रवेश एवं हरियाली राजस्थान के तहत सभी विद्यालयों में पौधारोपण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के द्वारा प्रति पटवारी को आपसी सहमति से 5 बंटेवार सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों से संवाद कर उनके द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। इस दौरान एसडीएम दामोदर सिंह, तहसीलदार नीरज सिंह, विकास अधिकारी, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

केलनिया शिविर में 20 लोगों को मिले पट्टे, हक मिला, भरोसा बढ़ा

हनुमानगढ़/रावतसर, (रॉयल पत्रिका)। रावतसर ब्लॉक की ग्राम पंचायत केलनिया में शुक्रवार को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शिविर ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान कर मिसाल पेश की। शिविर में 20 लोगों को आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर उन्हें मालिकाना हक सौंपा गया।

लाभार्थी हेतराम पुत्र लादूराम और इमरती ने बताया कि उनके पास वर्षों से अपने घर के भूखंड के दस्तावेज नहीं थे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और अन्य कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही शिविर की सूचना भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में उन्हें मिली, वे उपस्थित हुए। मौके पर ही उपखंड अधिकारी संजय कुमार, नायब तहसीलदार पुष्पा बेनिवाल, सहायक विकास अधिकारी अन्नतराम गोदारा, ग्राम पंचायत प्रशासक केसराराम एवं



ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार की संयुक्त कार्यवाही से उन्हें पट्टा प्रदान किया गया। पट्टा हाथ में मिलते ही दोनों के चेहरे पर राहत और उम्मीद की चमक दिखी। शिविर में प्रधानमंत्री मूद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 13 किसानों को मूद्रा कार्ड वितरित किए गए। इन कार्डों की सहायता से किसानों को खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी और वे संतुलित उर्वरक प्रयोग कर बेहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे। राजस्व

विभाग की ओर से पटवारी मनीषा मीणा द्वारा 25 लंबित नामांतरण प्रकरणों को मौके पर ही निस्तारित कर लाभार्थियों को राहत दी गई। इस त्वरित कार्यवाही से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और योजनाओं के प्रति सहभागिता का भाव और गहरा हुआ। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जिला प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे शिविर सरकार की जनकल्याणकारी सोच को धरातल पर साकार कर रहे हैं।

30 सितंबर 2025 तक जिले में चलेगा जन सुरक्षा योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान

शिविर में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित होंगे कार्य

बारां, (रॉयल पत्रिका)। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक त्रैमासिक देशव्यापी वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान (जन सुरक्षा योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान) संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही पात्र नागरिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। अभियान के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत वर्तमान निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः सत्यापन, जिन व्यक्तियों के अर्भी तक बैंक खाते नहीं हैं, उनके नए बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन किया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला कलक्टर रोहितलाल सिंह तोमर ने जिलेवासियों से कहा है कि इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय रूप से भाग



लें और बैंकिंग व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं तथा अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, बैंक शाखा या जिला अग्रणी बैंक कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। इन योजनाओं में यह मिलेगा लाभ

करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान आधारित स्थायी मासिक पेंशन मिलेगी। पीएमजेजेवाई एवं पीएमएसबीवाई के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से एसएमएस एवं मिस कॉल से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यहां आयोजित होंगे शिविर - 9 जुलाई को अंता ब्लॉक की ग्राम पंचायत बमुलिया माताजी, 11 जुलाई को बमुल्याकलां, 14 जुलाई को बड़गांव, 16 जुलाई को बड़गांव, 17 जुलाई को भोज्याखेड़ी, 21 जुलाई को बिजौरा, 22 जुलाई को चहेड़िया, 28 जुलाई को जयनगर एवं 31 जुलाई को काचरी में शिविर आयोजित होंगे।

अजमेर दरगाह में 40 किलो चांदी का ताजिया लोगों के लिए बना कौतूहल

- मुहर्रम के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

अजमेर। इस्लामी इतिहास में मुहर्रम को सत्य और ईसाफ की राह पर चलने की मिसाल माना गया है। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत आज भी मानवता को बलिदान, धैर्य और न्याय की प्रेरणा देती है। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही अजमेर शरीफ की फिजा में राम-ए-हुसैन की सदा गूंजने लगी है। इस मौके पर सूफ़ी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बना 40 किलो चांदी का ताजिया आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। दरगाह शरीफ के खादिम सैयद अलीम चिश्ती सजन बताते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज को इमाम हुसैन का वंशज माना जाता है, इसीलिए मुहर्रम का खास महत्व अजमेर दरगाह में देखने को मिलता है। इस चांदी के ताजिए को लेकर खिदमतगार डॉक्टर सैयद नजमुल हसन चिश्ती बताते हैं कि एक अकीदतमंद ने अपनी मुराद पूरी होने पर यह ताजिया पेश किया था। इसे आगरा के कारीगरों ने अजमेर

में रहकर तैयार किया था। अब यह ताजिया न सिर्फ अजमेर, बल्कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का प्रतीक बन गया है। मकबरा

हॉल में सजाए गए इमाम बारगाह में लोग बड़ी तादाद में पहुंचकर जिक्र-ए-कब्राला कर रहे हैं और मन्त्रों, मुरादों मांग रहे हैं। पीढ़ियों से निभ रही परंपरा और सांस्कृतिक साझेदारी राजस्थान के अन्य इलाकों में भी मुहर्रम को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। डीडवाना और कुचामन सिटी जैसे कस्बों में पीढ़ियों से ताजिए बनाने की परंपरा कायम है। कारीगर मुबारक अली, मोहम्मद निज़ामुद्दीन और नाथू शाह जैसे लोग इसे केवल एक पेशा नहीं, बल्कि इबादत मानते हैं। यह परंपरा आज भी हिंदू-मुस्लिम

एकता की मिसाल पेश करती है। प्रशासन की सतर्कता और भाईचारे की अपील ताजिए के जुलूसों को लेकर जिला प्रशासन ने सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की हैं। अजमेर पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। इस्लामी इतिहास में मुहर्रम को सत्य और ईसाफ की राह पर चलने की मिसाल माना गया है। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत आज भी मानवता को बलिदान, धैर्य और न्याय की प्रेरणा देती है।

एकता की मिसाल पेश करती है। प्रशासन की सतर्कता और भाईचारे की अपील ताजिए के जुलूसों को लेकर जिला प्रशासन ने सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की हैं। अजमेर पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। इस्लामी इतिहास में मुहर्रम को सत्य और ईसाफ की राह पर चलने की मिसाल माना गया है। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत आज भी मानवता को बलिदान, धैर्य और न्याय की प्रेरणा देती है।

दिव्यांग मांगीलाल के लिये शिविर खुशियां लेकर आया मिला योजनाओं से सम्बल

पाली, (रॉयल पत्रिका)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत पंचायत समिति पाली की ग्राम पंचायत मुख्यालय सोडावास शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मांगीलाल पुत्र हेमाराम सिखरी निवासी सोडावास के लिये अपार खुशियां लेकर आया, मांगीलाल पांव से दिव्यांग है, अतः असमर्थता के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित था उसने आज शिविर में

भविष्य में सरकारी लाभ की राह आसान हो गई है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विशाल सीपा मौजूद रहे जिन्होंने विभिन्न कार्ड सौंपे। इतने का एक साथ होने पर मांगीलाल भावुक व खुश हुआ और चेहरे पर मुस्कान छा गयी। मांगीलाल ने इन कामों के लिये राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रशासन को धन्यवाद दिया।

अजमेर दरगाह में 40 किलो चांदी का ताजिया लोगों के लिए बना कौतूहल - मुहर्रम के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

जिला कलक्टर ने किया अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण



सवाई माधोपुर, (रॉयल पत्रिका)। जिले में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण सवाई माधोपुर शहर सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर काना राम ने राजबाग पुलिया, सिटी बस स्टैंड, गोपाल जी का मंदिर पुलिया, लटिया नाला, खेरदा ब्रिज क्षेत्र सहित अन्य जलभराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली तथा मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को त्वरित राहत कार्य, जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के कारण उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में रहें। जिला कलक्टर ने सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ तथा बाढ़ राहत से जुड़े समस्त विभागों को

24 घंटे सक्रिय रहने और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने लटिया नाले के तेज बहाव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी व अन्य आवश्यक सुविधाओं की शीघ्र बहाली के निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने आमजन से अपील की कि संभावित भारी बारिश को देखते हुए निचले क्षेत्रों और जर्जर भवनों में रह रहे नागरिक सतर्क रहें एवं आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित हो जाएं। जिला प्रशासन की ओर से किसी भी आपात स्थिति में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्षा के दूरभाष नंबर 07462-220602, 07462-220201 तथा टोल फ्री नंबर 1070 पर तत्काल संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर अनूप सिंह, नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रहमत फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंदों को फल और जूस वितरण कर

-कब्रला में शहीदों की शहादत को याद किया गया

चूरू, (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर भारतीय रोड रहमत फाउंडेशन के उपसंचालक सोहेल अहमद चौहान ने बताया कि ये प्रोग्राम मोहम्मद इस्माइल चौहान की ओर से करवाया गया और इसके साथ ही मोहम्मद का पर्व हमें जो हमारे पास है उसमें ही सबर और शुक्र करने का पैगाम

देता है और अपने हक के लिए लड़ना सीखाता है और इसके साथ ही आपसी भाईचारे का पैगाम देता है इस प्रोग्राम में मोहम्मद जुनेद अली, अहमद सुहेल चौहान, अब्दुल अजीज, अली अहमद, ओवेश राजा, मोहम्मद समीर हसन और रहमत फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे।

युवा नेता गौरव सारण ने नाले के बहाव क्षेत्र से मलबा हटाने की मांग

सांचौर, (रॉयल पत्रिका)। शहर के बड़सम पुलिया के नीचे से बारिश के पानी का बहाव क्षेत्र है। बहाव क्षेत्र में हावू टेकेदार द्वारा अवैध डम्पिंग मलबा डाल कर बहाव क्षेत्र को रोक दिया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। युवा नेता गौरव सारण ने बताया कि बहाव क्षेत्र को रोकने से व मलबा डालने से शहर में बाढ़ का पानी एक साथ आएगा और व्यापारियों और आमजन को भारी नुकसान होगा। ज्ञापन सौंपकर युवा नेता गौरव सारण ने बताया कि प्रशासन इसे मामले में तुरन्त हस्तक्षेप कर मलबे को हटवाए और ठेकेदार को डम्पिंग मलबा भविष्य में उक्त जगह पर

न डालने के लिए पांबंद करे। सांचौर क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए मलबे को अतिशीघ्र हटाने की मांग की गई। इस दौरान केसराम भील, पूनमावाम पुरोहित, भारमल देवासी, भवजी बन्ना, राजुराम, आसुराम जाट, रमेश जाट, परागाराम, महेंद्र माली, हनीफ खॉं, बरकत खॉं, रणजीत सहित कई युवा कांग्रेस मौजूद थे।

प्रदेश महासचिव ने सेड़िया शिविर प्रभारी को दिया ज्ञापन



सांचौर, (रॉयल पत्रिका)। हमन राइट जस्टिस एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव खलीफा मोहम्मद बक्ष ने पं.दीनदयाल उपाध्याय शिविर प्रभारी सेड़िया को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सरनाऊ के ग्राम पंचायत सेड़िया की मुख्य सड़क जर्जर हो चुकी है लम्बे समय से मांग करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश के मौसम में पता ही नहीं चलता सड़क में गड्डे है या गड्डे में सड़क जगह-जगह बड़े गड्डे होने के कारण आने जाने वाले आम राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात में पानी के भराव के कारण आम नागरिकों के साथ विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को अत्यधिक दलदली कीचड़ से बच्चों में डर का माहौल बना रहता है। सांगरोल नाडी से तुलशानियों की ढाली तक कच्चा रास्ता होने से बारिश

के मौसम अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ के भराव के कारण कई बार विद्यालय जाने वाले बच्चे हादसे का शिकार बन रहे हैं। नारायणपुरा के ग्रामीणों ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनेक्शन तो कर दिया परन्तु एक बूंद पानी का नहीं आया समस्त ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण के साथ पानी की सप्लाई सुचारू की जावे। ताकि ग्रामीणों एवं विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सके। इस मौके पर नबी बक्स भाटी, अहमद अली राहुमा, कासम खान, यूसीन खॉं, कोमलशाह, हनीफशाह, भीखुशाह, अल्लाबक्षशाह, रहमतुल्लाह शाह, समन्दरशाह, दिलीप कुमार भील, कालु राम, प्रकाश कुमार भील, खुबाराम भील सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

शेखावाटी अंचल की तीन प्रमुख निकाय झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा के न्याय मित्र

-के के गुप्ता दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे

झुंझुनू, (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश के शेखावाटी अंचल की निकाय नगर परिषद झुंझुनू, नगर पालिका नवलगढ़ और नगर पालिका मंडावा के लिए माननीय जिला लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के के गुप्ता आगामी 12 और 13 जुलाई को दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। न्याय मित्र गुप्ता के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी) एकीकृत कार्यालय उदयपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 12 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक उक्त तीनों निकाय में "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत निर्देश अनुसार किये जा रहे कार्यों का सघन निरीक्षण किया जायेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। शहर में गंदगी कचरा कही पर नहीं दिखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नालियों की सफाई, अतिक्रमण - (सड़कों पर), नाईट स्वीपिंग, सड़कों पर जानवर, सड़कों की स्थिति, सड़कों पर लाईटें, कचरा याईटें, सड़कों पर पानी भराव, प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध, वार्डों में कर्मचारी सफाई, हवेलियों का जिर्णोधर, सार्वजनिक टॉयलेटों की सफाई दिन में, रोड़ लाइटें,

आमजन की प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, दीवारों की सफाई, पेन्टिंग कार्य सहित अन्य प्रमुख घटक का निरीक्षण किया जाएगा। तीनों निकायों के जिम्मेदार अधिकारियों को भी विशेष निर्देश जारी



आमजन द्वारा स्वच्छता, गंदगी एवं रोड़ लाइटों के बारे में भारी शिकायतें की जा रही है जो निम्न है, शहर में खाली पड़े भूखण्ड गंदगी से भरे पड़े हैं पानी भरा पड़ा है उनमें जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं जिनसे आमजन परेशान है। भूखण्ड मालिकों को नोटिस जारी कर अविलम्ब भूखण्ड को साफ करवाया जावे तथा भूखण्ड साफ न करने कानूनी कार्यवाई की जावे। अधिकतर रोड़ लाइट्स लम्बे समय से बंद पड़ी है तत्काल चालू करवाई जावे। जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। जगह जगह गंदगी फैल रही है। उपरोक्त कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा तथा माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। न्याय मित्र गुप्ता ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में यह सभी शहर प्रमुख पर्यटक नगरी भी है। देश एवं विदेशी पर्यटक यहां भारी संख्या में आते हैं। नगर की आम जनता द्वारा यह बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है कि वर्तमान में वर्षा ऋतु के समय में जगह-जगह

पानी भर रहा है, सीवरेज का कार्य व्यवस्थित नहीं होने से गंदगी पानी में फैल रही है तथा घरों में गंदा पानी जाने की वजह से मौसमी बिमारियां फैलने की आशंका है। ऐसी स्थिति में सीवरेज लाईन को व्यवस्थित करवाने के साथ -साथ जहां-जहां कॉलोनी में पानी भर रहा है उसके निकासी की तत्काल व्यवस्था करना जनहित में आवश्यक है। वहीं, आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू को यह भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं कि न्याय मित्र गुप्ता दिनांक 13 जुलाई को निरीक्षण बाद मारवाड़ी युवा मंच झुंझुनू शाखा के स्थापना दिवस समारोह साय 6 बजे स्थान मुनि आश्रम सभागार, पंचदेव मंदिर एवं एमजी मील के पास कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। कार्यक्रम हजारों लोग हिस्सा लेंगे। मुनि आश्रम सभागार, मंदिर के आस पास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे।

सफलता की कहानी ग्रामीणों के लिये राहत लाये हैं शिविर

- रेखा को मिला शिविर में आर्थिक संबल सामाजिक सुरक्षा पेंशन

पाली, (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिये पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा में ग्रामों में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं जो ग्रामीणों के लिये राहत लेकर आया है साथ ही ग्रामीणों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है और अनेक योजनाओं में उनको लाभ मिल रहा है। ऐसा ही आज हुआ ग्राम पंचायत कोट बालियान, तहसील बाली पाली की रहने वाली रेखा के साथ। रेखा पत्नी गोविन्द जाति कालबेलिया ग्राम कोट बालियान की निवासी है जो उनके पति गोविन्द की चार माह पूर्व मृत्यु हो चुकी। उन्होंने बताया कि उनके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं और स्वयं व मरे बच्चों का मैं मजदूरी करके मुश्किल से भरण-पोषण करती हूँ और मुझे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बहुत आवश्यकता थी।



उन्होंने आज शिविर के बारे में पता चला तो वे शिविर में अपनी व्यथा लेकर पहुंची। उन्होंने ग्राम पंचायत में शिविर प्रभारी मनमोहन सिंह नायब तहसीलदार के समक्ष समस्या बताई। सिंह ने ग्राम विकास अधिकारी रामचन्द्र यादव व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के केलशा कुमार को सामाजिक सुरक्षा

पेंशन बँटवें में आवेदन कर पेंशन स्वीकृत करवाने का कहां और ईमिन्न से आवेदन करवाकर रेखा की पेंशन आज कैप में हाथी हाथ जारी की गयी। पेंशन जारी करने पर रेखा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गयी और प्रशासन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया।

अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज

-RBI का नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने लोन लेने वालों को राहत दी है। दरअसल, RBI ने प्लोटींग इंटररेस्ट रेट वाले लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकाता है, तो बैंक ये चार्ज वसूलता था। नया नियम सभी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों, खासकर होम लोन और MSE लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।



RBI के फैसले से किसे फायदा मिलेगा ?

इस फैसले से उन व्यक्तियों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने नॉन कॉमर्शियल काम के लिए प्लोटींग रेट पर लोन लिया है। भले ही किसी व्यक्ति ने अकेले लोन लिया हो या को-ऑर्बिगेंट के साथ लोन लिया हो। ऐसे सभी लोन पर कोई भी बैंक या NBFC प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस के लिए लोन लिया है या किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज (MSE) ने लोन लिया है, तब भी कॉमर्शियल बैंक प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाएंगे। हालांकि, यह छूट कुछ खास कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगी।

4.टियर-4 अर्बन को-ऑर्परेटिव बैंक

5.NBFC-अपर लेयर (NBFC-UL)

6.ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन

₹50 लाख तक के लोन पर भी राहत

अगर किसी व्यक्ति या MSE को ऊपर दिए गए इंस्टीट्यूशंस से ₹50 लाख तक का लोन मिला है, तो उस पर भी प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। इसमें टियर-3 अर्बन को-ऑर्परेटिव बैंक, स्टेज और सेंट्रल को-ऑर्परेटिव बैंक और NBFC-अपर लेयर (NBFC-ML) शामिल हैं।

RBI ने यह फैसला क्यों लिया ?

RBI ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि कई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस प्री-पेमेंट चार्ज को लेकर अलग-अलग पोलिसी अपना रही थीं। इससे ग्राहकों में भ्रम और विवाद की स्थिति बन रही थी। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस लोन एप्रोमेंट में ऐसे रिस्ट्रिक्टिव

क्लॉज शामिल कर रहे थे। जिससे ग्राहक कम ब्याज दर वाले ऑप्शन पर स्विच न कर सके।

RBI ने कहा कि यह राहत लोन चुकाने के सोर्स पर निर्भर नहीं होगी। यानी चाहे लोन का पार्ट पेमेंट हो या पूरा लोन पेमेंट हो और फंड का सोर्स कोई भी हो, अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही किसी भी तरह का लॉक-इन पीरियड अनिवार्य नहीं होगा।

फिक्स्ड टर्म लोन पर क्या फायदा होगा?

नए नियमों के मुताबिक, फिक्स्ड टर्म लोन पर अगर प्री-पेमेंट चार्ज लगाया भी जाता है, तो वह सिर्फ प्री-पे की गई राशि पर बेस्ड होना चाहिए। वहीं, ओवरड्राफ्ट या केश क्रेडिट के मामलों में नियम थोड़ा अलग है। अगर लोन लेने वाला समय से पहले रिन्यूएबल करने की सूचना देता है और तय तारीख पर लोन खत्म कर देता है, तो कोई प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जाएगा।

की - फैक्ट्स स्टेटमेंट में पूरी डिटेल्स जरूरी RBI ने यह भी निर्देश दिया है कि प्री-पेमेंट चार्ज से जुड़े सभी नियमों की जानकारी लोन एक्सेप्टेंस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और की - फैक्ट्स स्टेटमेंट (KFS) में दी जानी चाहिए। अगर KFS में कोई चार्ज पहले से मंशन नहीं है, तो बाद में उसे वसूल नहीं किया जा सकता। यह फैसला ग्राहकों की ट्रांसपैरेंसी और कॉम्प्लेटिव बैंकिंग सर्विसेज की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

ग्राहकों के लिए RBI के फैसले का मतलब

RBI के इस फैसले का मतलब यह है कि अगर आपने प्लोटींग इंटररेस्ट रेट पर लोन (जैसे होम लोन) लिया है और आप उसे थोड़ा या पूरा तय समय से पहले चुकाना चाहते हैं, तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी आपसे कोई प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूल पाएंगी। इसमें शर्त यह है कि लोन 1 जनवरी 2026 या उसके बाद मंजूर या रिन्यू हुआ हो। बैंक या कंपनी ग्राहकों पर यह चार्ज इसलिए लगाते थे, ताकि ग्राहक किसी और बैंक के सस्ते लोन पर स्विच न कर सकें या प्री-पेमेंट न करें। इससे उन्हें पूरा ब्याज कमाने का मौका मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर महंगे हो सकते;

बजाज, एथर और TVS घटाएंगी प्रोडक्शन

- चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैनेट की शॉर्टेज का असर

चीन की ओर से कीमती धातुओं (रेयर अर्थ मटेरियल) के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का असर भारतीय EV मार्केट पर दिखने लगा है। देश में टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियां बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और TVS मोटर प्रोडक्शन घटाने जा रही हैं। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 4 महीने से चीन से इंपोर्ट की जाने वाली रेयर अर्थ मैनेट की कमी से भारतीय कंपनियां जूझ रही हैं। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए बेहद जरूरी हैं और बिना इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में दिक्कत हो रही है। प्रोडक्शन घटने से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कीमतें बढ़ सकती हैं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियां

बजाज ऑटो: भारत की दूसरी सबसे बड़ी EV टू-व्हीलर कंपनी बजाज अपने प्रोडक्शन को आधा करने जा रही है। उनके चेतक लाइन पर पहले से दिक्कतें शुरू हो गई हैं।

एथर एनर्जी: बेंगलुरु की ये कंपनी 8-10% प्रोडक्शन घटाने की प्लानिंग कर रही है।

टीवीएस मोटर: पिछले 3 महीने से सेल्स में नंबर वन रहने वाली कंपनी भी प्रोडक्शन कम करने को मजबूर है। टीवीएस प्रवक्ता ने कहा, 'EV सप्लाय वेन में मैग्नेट की कमी से शॉर्ट और मीडियम टर्म में चुनौतियां बढ़ गई हैं। ओला इलेक्ट्रिक: प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओला के पास 5-6 महीने का मैग्नेट स्टॉक है और वे प्रोडक्शन



बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। ओला प्रवक्ता अनुसार, हमारे प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं है। ये 4 कंपनियां भारत में बिकने वाले 80% इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाती हैं।

चीन के साथ बातचीत कर रही हैं केंद्र सरकार

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और केंद्र सरकार चीन के साथ बातचीत कर रही हैं, ताकि मैग्नेट की आपूर्ति फिर से शुरू हो। इसके अलावा, वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों से भी सप्लाय के लिए बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है।

चीन की पाबंदियां बनीं रहीं, तो महंगी होगी ईवी

अगर चीन की पाबंदियां बनीं रहीं, तो ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों पर

इसका असर देखने को मिलेगा। कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे गाड़ियों के दाम भी ऊपर जा सकते हैं। भारत सहित सभी बाजारों में भी इसका असर धीरे-धीरे दिखेगा। भारत में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन से इंपोर्ट जल्द शुरू न हुआ तो इलेक्ट्रिक और ICE वाहनों के कारखानों का प्रोडक्शन रुक सकता है।

भारत में मैग्नेट की सप्लाय के पास 6 से 8 हफ्तों की सप्लाय

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में EV ओरिजिनल इकिपमेंट मैग्नेट की सप्लाय बची है, वहीं CNBC-TV18 को टीवीएस मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सुदर्शन वेणु ने बताया था कि चीन के प्रतिबंधों का असर जून या जुलाई के उत्पादकों में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय EV उत्पादकों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है।

गाड़ी में रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल कहां होता है

रेयर मटेरियल्स की माइनिंग में चीन की करीब 70% हिस्सेदारी बता दें कि ग्लोबल लेवल पर रेयर मटेरियल्स की माइनिंग में चीन की हिस्सेदारी करीब 70% और प्रोडक्शन में करीब 90% तक है। चीन ने हाल ही में अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं (रेयर अर्थ मटेरियल) के निर्यात पर रोक लगा दी थी। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए हैं। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम हैं।

भारत में जल्द मिलेगा हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट IN-SPACE चेंजरमैन बोलें

- स्टारलिनिक को कुछ दिनों में मिल जाएगा फाइनल अप्रूवल

इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स कुछ ही दिनों में स्टारलिनिक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है। स्पेस रेगुलेटर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी, IN-SPACE के चेंजरमैन डॉ. पवन गोयनका ने कहा है कि स्टारलिनिक को लेकर ज्यादातर रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।



डॉ. गोयनका के मुताबिक, अब सिर्फ कुछ अंतिम मंजूरीयां बाकी हैं, जो अगले कुछ दिनों में मिल जाएंगी। हाल ही में स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट विन शॉटवेल भारत आई थीं।

उन्होंने डॉ. गोयनका से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में स्टारलिनिक की लॉन्चिंग से जुड़े बड़े हुए मुद्दों पर बात हुई थी।

हालांकि, डॉ. गोयनका ने यह भी साफ किया कि मंजूरी मिलने के बाद भी Starlink सर्विस को शुरू होने में कुछ महीने और लग सकते हैं। उन्होंने कहा ऑथराइजेशन के बाद भी कई टेक्निकल और प्रोसीजरल स्टेप्स पूरे करने होंगे। गोयनका ने सभी बॉर्डर NDTV को दिए इंटरव्यू में कहीं हैं।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मिल चुका लाइसेंस

इससे पहले स्पेसएक्स को स्टारलिनिक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल चुका है। अब उसे सिर्फ IN-SPACE के अप्रूवल का इंतजार है। स्टारलिनिक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वनवेब और रिलायंस जियो को मंजूरी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिनिक भारत में 840 रुपये में महीनेभर अनलिमिटेड डेटा देगा। आधिकारिक तौर पर मस्क की कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है।

सैटेलाइट्स से आप तक कैसे पहुंचेगा इंटरनेट?

सैटेलाइट धरती के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कनेक्शन को संभव बनाती है। सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। लेटेंसी का मतलब उस समय से होता है जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरे

तक पहुंचाने में लगता है। स्टारलिनिक फिट में स्टारलिनिक डिश, एक वाई-फाई राउटर, पॉवर सप्लाय केबल्स और माउंटिंग ट्राइपॉड होता है। हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखना होगा। iOS और एंड्रॉइड पर स्टारलिनिक का ऐप मौजूद है, जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता है।

जून 2020 में सरकार ने IN-SPACE स्थापित किया था

डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने जून 2020 में IN-SPACE को स्थापित किया था। यह स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को रेगुलेट करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल-विंडो एजेंसी के रूप में काम करती है। IN-SPACE नॉन-गवर्नमेंटल एंटीटीज के लिए लाइसेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेरिंग और स्पेस बेस्ड सर्विसेज को बढ़ावा देने का काम भी करती है।

इस हफ्ते सोने-चांदी में रही तेजी: सोना ₹1,237 बढ़कर ₹97021 पर पहुंचा, चांदी ₹2387 महंगी

सोने-चांदी में तेजी, दाम नई ऊंचाई पर: इस साल ₹1 लाख से ऊपर जाने की संभावना

इस हफ्ते सोने-चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 28 जून को सोना 95,784 रुपए पर था, जो अब (5 जुलाई) को 97,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,237 रुपए बढ़ी है।

वहीं, चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,05,193 रुपए पर थी, जो अब 1,07,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2,387 रुपए बढ़ी है। 18 जून को चांदी ने ₹1,09,550 और सोने ने ₹99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था।

4 महानगरों में 10 ग्राम सोने की कीमत

- 1.दिल्ली: 24 केरट सोने की कीमत ₹98,980 और 22 केरट सोने की कीमत ₹90,970
- 2.मुंबई: 24 केरट सोने की कीमत ₹98,830 और 22 केरट सोने की कीमत ₹90,600
- 3.कोलकाता: 24 केरट सोने की कीमत ₹98,830 और 22 केरट सोने की कीमत ₹90,600
- 4.चेन्नई: 24 केरट सोने की कीमत ₹98,830 और 22 केरट सोने की कीमत ₹90,600
- 5.भोपाल: 24 केरट सोने की



कीमत ₹98,880 और 22 केरट सोने की कीमत ₹90,650

इस साल अब तक ₹20,859 महंगा हुआ सोना

इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 केरट सोने का दाम 76,162 रुपए से 20,859 रुपए बढ़कर 97,021 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 21,563 रुपए बढ़कर 1,07,580 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 रुपए महंगा हुआ था।

इस साल ₹1 लाख 3 हजार तक जा सकता है

सोना केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि जियो पॉलिटेकल टेंशन बने हुए है। इजराइल और ईरान के बीच भी जंग शुरू हो गई है।

इससे गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में इस साल सोना 1 लाख 3 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी इस साल 1 लाख 30 हजार रुपए तक जा सकती है।

सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें

हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अस्कान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह होता है- AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने केरट का है।

लेक्चरर-कोच एजाम ग्रुप-B पेपर की मॉडल ANSWER-KEY जारी

कैंडिडेट्स 7 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, 26 से 29 जून तक हुए थे एजाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही प्राध्यापक एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतिम ग्रुप बी के विषय जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एवं फिजिक्स विषय की मॉडल ऑंसर-की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त विषयों की परीक्षाओं का आयोजन 26 से 29 जून 2025 तक किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल ऑंसर-की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 5 से 7 जुलाई 2025 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के



अनुसार ही दर्ज करनी होगी। परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिकेटेड) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही दर्ज करानी होगी। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

100 रुपए होगी फीस, ये रहेगा ऑनलाइन प्रोसेस

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (केशन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्न पर आपत्तियां दर्ज करा सकेगा।

DSSSB ने 2,119 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी; 8 जुलाई से शुरू आवेदन

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने जेल वार्डर सहित 2,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

केटेगरी वाइड वैकेंसी डिटेल्स :

- अनारक्षित : 892 पद
 - ओबीसी : 558 पद
 - एससी : 312 पद
 - एसटी : 148 पद
 - ईडब्ल्यूएस : 209 पद
- एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :**
- 10वीं, 12वीं, संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री,
- एज लिमिट :**
- जेल वार्डर/लैब टेक्नीशियन, मलेरिया इन्स्पेक्टर, फार्मासिस्ट : 18-27 वर्ष
 - पीजीटी/शिक्षक : 30 वर्ष
 - आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट : 18-32 वर्ष

रेलवे में रिटायर्ड ऑफिसर के लिए निकली भर्ती

-एज लिमिट 65 साल, बिना एजाम के होगा सिलेक्शन



सेंट्रल रेलवे ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यह भर्ती मुंबई और उससे संबंधित डिजीवन के लिए है।

वैकेंसी डिटेल्स :

- मुख्यालय जनरल, स्टोर्स और ट्रेकिंग अकाउंट्स: 24 पद
- ST. DFM. C&AO : 03 पद
- Dy.FA&CAO (W) माहुंगा: 01 पद
- Dy.FA&CAO (C) दौंडिया चौरा: 01 पद

योग्यता :

यह भर्ती रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर चुके रिटायर्ड स्टाफ के लिए है।

एज लिमिट :

अधिकतम 65 साल सिलेक्शन प्रोसेस : एक्सपीरियंस के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा।

सैलरी :

जारी नहीं

ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट crindianrailways.gov.in पर जाएं। फार्म भरकर इस पते पर भेजें : हेड कार्टर एडमिन सेक्शन पीएफए ऑफिस, मुंबई सीएसएमटी

झारखंड के दो प्रवासी मजदूरों की विदेश में हुई मौत, हफ्तों गुजरने के बाद भी घरवालों को नहीं मिला है शव

सऊदी अरब और कुवैत में दो भारतीय मजदूरों की मौत के बाद झारखंड के उनके गाँव में शवों का इंतजार किया जा रहा है।

झारखंड। यह मामला हजारीबाग ज़िले के बिष्णुगढ़ प्रखंड स्थित जोबर पंचायत के बनखारों गाँव का है। इनमें से एक मजदूर की मौत हुए 40 दिन हो चुके हैं जबकि दूसरे की मौत भी करीब 20 दिन पहले हुई थी। इनका शव आज तक परिवार वालों तक नहीं पहुँचा है। यहाँ के एक प्रवासी मजदूर धनंजय महतो की मौत सऊदी अरब में 24 मई 2025 को हो गई थी। वहीं 15 जून को दूसरे प्रवासी रामेश्वर महतो ने कुवैत के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। दोनों ही मजदूरों के परिजन शव वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मामला सुर्खियों में आने के बाद झारखंड सरकार का श्रम विभाग विदेश मंत्रालय के अधीन आने वाले लेबर सेल प्रोटेक्टर ऑफ़ इमिग्रेंट के संपर्क में है। इसके साथ ही राज्य का श्रम विभाग सऊदी अरब और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क में है।



धनंजय महतो सऊदी अरब की निर्माणधीन परियोजना नियम मंगा सिटी में ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर लगाने का काम कर रहे थे। इसके लिए उन्हें चालीस हजार रुपए वेतन मिलता था। यहाँ साइट से कुछ दूरी पर मजदूरों के रहने के लिए कंटेनर से बनी अस्थायी रिहायशी डॉर्मिटरी है। धनंजय यहाँ दूसरी मंजिल पर झारखंड के अन्य मजदूरों के साथ रहते थे। धनंजय महतो हमेशा साइट पर जाने से पहले अपनी पत्नी से सऊदी अरब के समय अनुसार सुबह के करीब पाँच बजे बात किया करते थे। उनकी पत्नी गीताजलि देवी के अनुसार 24 मई को वह हमेशा की तरह वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे। वह कहती हैं कि "अचानक उनका मोबाइल गिर कर बंद हो गया। दोबारा कॉल लगाने पर उनका मोबाइल स्विक ऑफ़ मिला।" वह आगे कहती हैं, "कुछ देर के बाद उनके साथी मुकेश महतो (बदला हुआ नाम) ने कॉल करते हुए बताया कि पति धनंजय नीचे गिर गए हैं।" बीबीसी ने मुकेश महतो से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी। मुकेश महतो के अनुसार, "24 मई को धनंजय महतो अपने कमरे

एवं मुआवज़े को लेकर बीबीसी ने लार्सन एंड टूब्रो कम्पनी के एच आर एडमिन आदित्य कुमार से बातचीत की। लेकिन उन्होंने किसी भी बिंदु पर बात करने से इंकार करते हुए कहा कि, "कम्पनी ने झारखंड के लेबर सेल को सूचित कर दिया है। आप उन्हीं से जानकारी लीजिए।" **क़रीब 40 दिनों से घर में नहीं मिला चूल्हा** गीताजलि देवी के घर क़रीब चालीस दिनों से चूल्हा नहीं जला है। घरवालों के लिए रिश्तेदारों के घर से दिन में एक समय का भोजन आता है। गीताजलि कहती हैं, "रिश्तेदारों के भोजन पर कब तक निर्भर रहेंगे। बात सिर्फ़ मेरी नहीं बल्कि सवाल पूरे परिवार का है जो मेरे पति की कमाई पर निर्भर था।" धनंजय महतो के परिवार में उनकी पत्नी, डेढ़ साल और 5 साल के दो बेटे, और धनंजय के माता-पिता हैं। वे घर के जिस एक कमरे में रहते थे उसकी खपरैल की छत हाल में हुई बारिश से गिर गई। ऐसे में धनंजय के बड़े भाई खिरोधर महतो ने हालात को देख कर हफ़्ते भर पहले अपना एक छोटा सा कमरा उन्हें रहने के लिए दे दिया। घर की चिंता में गीताजलि देवी कहती हैं, "आज नहीं तो कल इस कमरे को खाली करना पड़ेगा। अब तो पति भी नहीं है कि घर का बन सके।" धनंजय के घर में न तो शौचालय है और न ही पीने के पानी की कोई सुविधा। उनके माता-पिता को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती। **कुवैत से शव आने का इंतज़ार कर रहे रामेश्वर महतो के परिवार** इसी बनखारों गाँव में धनंजय महतो के घर से पांच सौ मीटर दूर रामेश्वर महतो का पक्का घर है जिसे उन्होंने कज़़ लेकर बनवाया था। इस घर में मोबाइल बजते ही उनके मां-पिता, पत्नी, दोनों बेटे और बहू फ़ोन की तरफ़ देखने लगते हैं कि शायद रामेश्वर महतो के शव के आने की सूचना आई है। वो कुवैत की एक कंपनी में 12 साल से नौकरी कर रहे थे।

फ़िलहाल उनकी सैलरी 36 हजार रुपये थी। रामेश्वर महतो की मौत 15 जून को कुवैत के अदान अस्पताल में भर्ती थे। जहाँ उनके करीब सहकर्मी रामकिशुन महतो ने अंत तक उनकी देखभाल की। रामकिशुन ने फ़ोन पर बीबीसी को बताया, "कुवैत के मबूला शहर के एक प्लेट की छठी मंजिल पर बनी डॉर्मिटरी में साथ रहने वाले रामेश्वर महतो 6 जून को हमेशा की तरह स्वस्थ थे। दोपहर में उन्होंने ही सभी के लिए चिकन पकाया। साथ मिलकर जब खाने बैठे तो अचानक उनका बाया हाथ और पैर निष्क्रिय होने लगे। रात बारह बजे तक तबीयत में सुधार नहीं होने पर साथियों ने उन्हें चार किलोमीटर दूर अदान अस्पताल में भर्ती कराया।" रामकिशुन ने रामेश्वर के गिरते स्वास्थ्य की सूचना कंपनी के सुपरवाइज़र और उनके परिवार को दी। रामकिशुन महतो समय-समय पर प्रमिला देवी को वीडियो कॉल से रामेश्वर महतो की झलक दिखा देते। वह कहती हैं, "पति लकवाग्रस्त हो चुके थे, अचेत अवस्था में उनको ऑक्सीजन लगी थी। हम असाहय इतनी दूर से सिर्फ़ प्रार्थना ही कर सकते थे।" लेकिन अब वह जीवित नहीं रहे।" प्रमिला आगे कहती हैं कि दो हफ़्ते गुज़रने के बावजूद कुवैत से शव नहीं आया। प्रमिला देवी के घर पर मौजूद प्रवासी मजदूर एक्टिविस्ट सिकंदर अली के अनुसार बिष्णुगढ़, बगोदर और डुमरी प्रखंड से लगभग दस हजार मजदूर भारत के बाहर काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि "विदेश में लेबर की मौत की सूचना अक्सर मिलती है। लेकिन उनके शव आने से लेकर मुआवज़ा मिलने तक के काम में बहुत देर हो जाती है।" रामेश्वर महतो के बहनोई टेकलाल महतो कहते हैं कि "शव के लिए मैंने बीडीओ से लेकर ज़िला उपायुक्त से मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया।"

दिल्ली। सरकार ने पुरानी कार पर बैन का फैसला वापस लिया, ईंधन मिलेगा-गाड़ी सौज नहीं होगी

दिल्ली। सरकार ने पुरानी कार पर बैन का फैसला वापस ले लिया है। अब 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा-गाड़ी सौज नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। CM रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इन पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन देने के फैसले को लेकर कई लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। **पुरानी गाड़ियों को सौज नहीं किया जाएगा** पुरानी कार को लेकर फैसले पर दिल्ली सरकार ने U टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होगी बल्कि वो दौड़ेगी क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1



जुलाई से लागू फैसलों को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी गाड़ियों को सौज नहीं किया जाएगा। **फिर किस आधार पर होगी वाहनों पर कार्रवाई?** CM रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा पुरानी कारों पर बैन के फैसले को वापस लेने के बाद पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। 10 साल से पुरानी डीजल कार, 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार और 15 साल से पुरानी स्कूटी, मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलेगा। **क्या था सरकार का पहले का फैसला?** दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हुआ था जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया था। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए थे। हालांकि, 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है।

पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या

-मिलने पहुंचे डिप्टी CM पर फूट मां का गुस्सा

पटना। बिहार में शुक्रवार रात साढ़े 11 बजे बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो मर्डर



खेमका गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक के पास कटराका निवास में रहते थे। आनन-फानन में परिजन उन्हें पटना के मेडिक्वर्स अस्पताल लेकर पहुंचे। जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौटे थे। वो जैसे ही अपार्टमेंट के पास पहुंचे, 'शूटर और शूटर को भेजने वालों की जानकारी मिल चुकी है। हत्या क्यों की गई ये भी लगभग सामने आ चुका है। जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।' डिप्टी CM विजय सिन्हा भी परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन पर खेमका का मां का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि 'मेरा बेटा भी BJP में था। मुझे ईसाफ चाहिए।' गोपाल खेमका का रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी बेटी के स्कॉटलैंड से आने का इंतजार किया जा रहा है। **अपार्टमेंट के गेट के सामने खेमका का मर्डर** पटना में गोपाल खेमका को उनके अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने अपराधी ने गोली मारी थी।

राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एनकाउंटर, पुलिस ने दो बदमाशों को मारी गोली



दिल्ली। राजधानी में गुरुवार की रात एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने इस एनकाउंटर में दो अपराधियों को धर दबोचा है। दोनों बदमाशों के घर में गोली लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को देर रात दिल्ली में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीया चली हैं। जानकारी के मुताबिक, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है। ये बदमाश नंदू गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस एनकाउंटर के बारे में सबकुछ। दरअसल, पुलिस को शक था कि ये बदमाश गैंगस्टर मनजीत महल के भोज पर गोली चलाने के मामले में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक, आरोपी नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पकड़े हुए बदमाशों का नाम विजय और सोमवीर बताया जा रहा है। **एनकाउंटर के बारे में क्या पता लगा?** गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे

दीपक की हत्या में शामिल दो अपराधियों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल देर रात शाहबाद डेयरी में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों की पहचान विजय और सोमवीर के रूप में हुई है और दोनों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ करेगी। **सराय काले खां में भी हुई थी मुठभेड़** इससे पहले दिल्ली के सराय काले खां में पुलिस और एसटीएफ का जवाइंट ऑपरेशन हुआ था। यहां पुलिस की एक कुख्यात बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने इस कार्रवाई में वांछित अपराधी ललित नेपाली को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक, बदमाश ललित नेपाली 2 दर्जन से अधिक वारदातों में शामिल था। कई कैसों में अदालतों द्वारा उसे भगोड़ी भी घोषित किया गया है। सराय काले खां में बदमाश और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी में एसपी, लाजपत नगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल-बाल बच गए। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बदमाश के पास से एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है।

मुंबई बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में तोड़फोड़

- MNS के कार्यकर्ताओं ने किया पथराव



मुंबई। मुंबई के वर्ल्ड में बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। इसका वीडियो भी सामने आया है। मुंबई के वर्ल्ड में बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। ये तोड़फोड़ राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने की है। बता दें कि हिंदी मराठी विवाद को लेकर शुक्रवार को बिजनेसमैन सुशील केडिया ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि वह मराठी भाषा नहीं सीखेंगे। इसके बाद तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। तोड़फोड़ के बाद सुशील केडिया ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया विवाद के बाद सुशील केडिया का माफ़ीनामा सामने आया है। उन्होंने अपने ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना के बाद एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और कहा, 'जिस तरह की स्थिति बनी थी, उसकी वजह से मानसिक तनाव में थे।' सुशील केडिया ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट सुशील केडिया ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया था, 'राज ठाकरे आपके सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे धमकाए जाने से मैं मराठी भाषा में पारंगत नहीं हो जाऊंगा। अगर मुझे मराठी भाषा की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं है, तो इतनी धमकियों के बीच और भी डर है कि अगर मैं कोई शब्द

सिफारिशें देगी। इसके अलावा, मराठी न बोलने को लेकर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। उदाहरण के लिए, मुंबई के मीरा रोड और पर्वड में मनसे कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों और एक वॉचमैन के साथ मारपीट की। क्योंकि उन्होंने मराठी में बात करने से इनकार किया। इन घटनाओं के वायरल वीडियो ने विवाद को और बढ़ाया। इसके जवाब में, सरकार ने 3 अक्टूबर को शास्तीय मराठी भाषा दिवस और 3-9 अक्टूबर को मराठी भाषा सप्ताह मनाने का ऐलान किया, ताकि मराठी की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा दिया जाए। विवाद में हिंदूत्व का मुद्दा भी जुड़ा, जब मंत्री निवेश राणे ने ठाकरे बंधुओं (उद्धव और राज) पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुस्लिम बहुल इलाकों में मराठी लागू करवाकर दिखाएं। यह विवाद मराठी अस्मिता, क्षेत्रीय राजनीति और भाषाई नीतियों के इर्द-गिर्द घूम रहा है, जिसमें हिंसा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

गलत तरीके से नहीं बोल पाया तो और हिंसा हो जाएगी। बात समझिए। धमकी नहीं, बल्कि प्यार लोगों को एक साथ लाता है।' सुशील केडिया ने पोस्ट किया था, 'ध्यान दें राज ठाकरे, मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मैं मराठी ठीक से नहीं जानता और आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने यह संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोगों को मराठी मानुष की देखभाल करने का दिखावा करने की अनुमति है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा।' महाराष्ट्र में मराठी भाषा से जुड़ा ताजा विवाद क्या है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा से जुड़ा ताजा विवाद 2025 में हिंदी को प्राथमिक स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के सरकारी फैसले से शुरू हुआ। इस नीति का शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने तीखा विरोध किया, इसे मराठी अस्मिता और संस्कृति पर हमला बताया गया। विरोध के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अप्रैल और जून 2025 के सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया, और एक नई समिति गठित की गई जो भाषा नीति पर